वर्ष 12 • अंक 245 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

सोमवार 2 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

तकनीक और सेवा प्रदाता फास्टैग के लिए तैयार

चंदा कोछड़ पृष्ठ 2

कोछड़ की याचिका पर सुनवाई आज

एक नज़र

घरेलू आंकड़े, वैश्विक संकेत तय करेंगे बाजार की चाल

शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि संबंधी पीएमआई सर्वेक्षण रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत निर्णयों, वाहनों की बिक्री के आंकड़ों तथा हॉन्क कॉन्ग पर लेकर चीन और अमेरिका के संबंधों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगी। विश्लेषकों ने यह राय प्रकट की है। विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह बाजार की चाल नवंबर में वाहनों की बिक्री के आंकड़ों तथा आरबीआई की नीतिगत बैठक से तय होगी। जीडीपी दर 4.5 प्रतिशत रह जाने पर भी बाजार प्रतिक्रिया दिखा सकता है।

एनबीसीसी और भूखंडों की कर सकती है पेशकश

सरकार नियंत्रित एनबीसीसी लिमिटेड दिवालिया हो चुकी रियल एस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली में कर्जदाताओं को अतिरिक्त जमीन की पेशकश कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी 20,000 फ्लैट पूरा करने की समय अवधि भी कम कर सकती है। सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि जिन फ्लैट के लिए दावे नहीं किए गए हैं और कुछ भूखंडों में मुनाफे में हिस्सेदारी देने की पेशकश के बदले कर्जदाताओं को अतिरिक्त जमीन दे सकती है। कंपनी 17 नवंबर को सौंपी बोली में निर्माणाधीन फ्लैट पूरा करने की चार वर्षों की समय सीमा भी कम कर रही है।

6 और हवाईअड्डों के निजीकरण की सिफारिश

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अमृतसर , वाराणसी , भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची हवाईअड्डों के निजीकरण की केंद्र से सिफारिश की है। एएआई ने 5 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में छह और हवाईअड्डों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि निदेशक मंडल के फैसला लेने के बाद नागर विमानन मंत्रालय को सिफारिश भेज दी गई है। एएआई देशभर में 100 से ज्यादा हवाईअड्डों का परिचालन करता है।

आईआईटी में प्लेसमेंट की शानदार शुरुआत

देश के प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के अंतिम चरण के पहले दिन रविवार को माइक्रोसॉफ्ट ने 1 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना वेतन (पैकेज) की पेशकश की। पहले दिन यह सबसे अधिक पैकेज की पेशकश करने वाली कंपनी रही। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट के बाद उबर, सेलफोर्स और कोहेसिटी ने कुछ शीर्ष आईआईटी परिसरों में इसी तरह के वेतन (1 करोड़ रुपये) की पेशकश की। प्लेसमेंट के आखिरी चरण की शुरुआत शानदार रही और पहले दिन बड़ी संख्या में कंपनियों ने ऑफर दिए।

संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए ऐक्सिस ने बढ़ाया प्रावधान

ऐक्सिस बैंक उन क्षेत्रों के कर्ज के लिए नियामकीय अनिवार्यता के मुकाबले दोगुनी रकम अलग रख रहा है, जिनकी पहचान बैंक ने दबाव वाले क्षेत्र के तौर पर की है। ऐसे क्षेत्रों के फंसे कर्ज के लिए बैंक मानक परिसंपत्ति प्रावधान एक फीसदी बरकरार रख रहा है, जबकि नियामकीय अनिवार्यता 0.40 फीसदी की है। बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीव आनंद ने यह जानकारी दी। एनपीए के उच्चस्तर और प्रावधान ने पिछले चार साल में ऐक्सिस बैंक समेत ज्यादातर बैंकों के लाभ पर असर डाला है। पृष्ठ 2

आज का सवाल

क्या कॉल दरें बढ़ाने से सुधरेगी दूरसंचार क्षेत्र की सेहत

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या देश की अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ चुकी है? हां **69.23%** नहीं **30.77%**

सस्ती कॉल व डेटा का दौर खत्म

वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने 40 फीसदी तक बढ़ाई दरें

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने आज अपनी मोबाइल सेवाओं की बढ़ी हुई दरों की घोषणा की। इन कंपनियों ने अपने शुल्क में 40 फीसदी तक बढ़ोतरी की घोषणा की। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 3 दिसंबर से लागू होंगी। जियो ने अनलिमिटेड वॉयस और डेटा के साथ नए प्लान शुरू करने की घोषणा की है। उसकी नई दरें 40 फीसदी महंगी होंगी और 6 दिसंबर से लागू होंगी।

एयरटेल की नई दरों में रोजाना 50 पैसे से 2.85 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। भारती एयरटेल के मुख्य विपणन अधिकारी शाश्वत शर्मा ने एक बयान में कहा, 'हमारे मोबाइल प्लान में उपभोक्ताओं को बहुत तवज्जो दी गई है और इसे एयरटेल के देशव्यापी 4जी नेटवर्क का बेहतर अनुभव का फायदा मिल रहा है।' जियो ने इस बयान में कहा कि वह उपभोक्ता सर्वोपरि के सिद्धांत पर टिकी हुई है और उनके नए प्लान में अन्य मोबाइल नेटवर्क पर कॉल करने के लिए उचित उपयोग नीति होगी। उसके नए ऑल इन वन प्लान 40 फीसदी महंगे होंगे लेकिन इनसे 300 फीसदी अधिक फायदे मिलेंगे।

■ एयरटेल ■ वोडाफोन-आइडिया — कीमत (रुपये में)

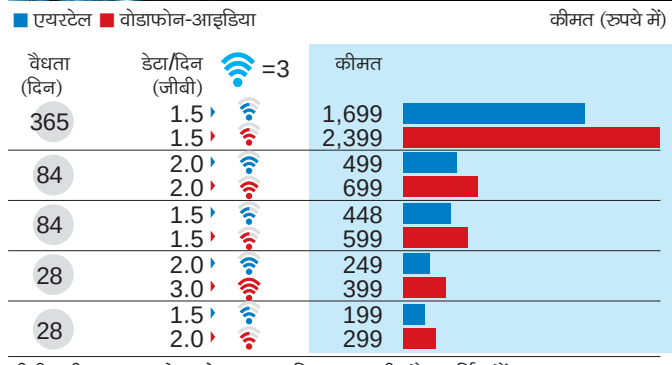

वैधता (दिन)	डेटा/दिन (जीबी)	कीमत
365	1.5 (एयरटेल)	1,699
	1.5 (वोडाफोन-आइडिया)	2,399
84	2.0 (एयरटेल)	499
	2.0 (वोडाफोन-आइडिया)	699
84	1.5 (एयरटेल)	448
	1.5 (वोडाफोन-आइडिया)	599
28	2.0 (एयरटेल)	249
	3.0 (वोडाफोन-आइडिया)	399
28	1.5 (एयरटेल)	199
	2.0 (वोडाफोन-आइडिया)	299

जीबी : गीगाबाइट, नोट : ये प्लान मासिक, छमाही और वार्षिक हैं
स्रोत : भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया

उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बीच वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारी घाटा हुआ था। इसके बाद दोनों कंपनियों ने अपनी दरें बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार को एजीआर बकाये का भुगतान शामिल करने के बाद एयरटेल को सितंबर तिमाही में 31,334 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा हुआ था। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी को 1,998 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा हुआ था।

दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया शामिल करने के बाद जुलाई-सितंबर तिमाही में 36,959 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा हुआ था। इस तिमाही में कंपनी को एजीआर सहित 30,774 करोड़ रुपये की चपत लगी। इससे कपंनी को सितंबर तिमाही में 50,922 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ जो किसी भारतीय कंपनी को एक तिमाही में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी को 4,974 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जबकि जून तिमाही में उसका घाटा 4,874 करोड़ रुपये था।

उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर को अपने फैसले में केंद्र सरकार से तीन महीने के भीतर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों से एजीआर के रूप में कुल 92,641 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को गैर-दूरसंचार राजस्व के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये का पिछला बकाया देना है। कंपनियां बकाये पर ब्याज और जुर्माने की राशि का माफ करने और तीन महीने की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है।

एयर इंडिया में निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

- रोडशो में विमानन कंपनियां, पीई फंडों और धनाढ्य निवेशकों ने की शिरकत
- संभावित निवेशकों की प्रतिक्रिया से सरकार को बिक्री सफल रहने की उम्मीद
- कर्ज को कम कर सरकार बिक्री प्रक्रिया को बना रही आकर्षक

सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियां, निजी इक्विटी फंडों और धनाढ्य निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। इससे सरकार को भी उम्मीद जगी है कि वह एयर इंडिया को इस बार बेचने में सफल रहेगी। इससे पहले दो बार उसे कोई खरीदार नहीं मिला था।

घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो, विस्तार और एयर एशिया इंडिया की टाटा संस, इंटरनैशनल एयरलाइंस ग्रुप और वैश्विक सॉवरिन एवं प्राइवेट फंडों- टेमासेक, केकेआर, वारबर्ग पिनकस ने ईवाई द्वारा आयोजित रोडशो में हिस्सा लिया था। ईवाई और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुंबई, सिंगापुर और लंदन में पांच रोडशो कर चुका है।

दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हम एयर इंडिया के विनिवेश की सही दिशा में हैं। हमें बिक्री प्रक्रिया को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया और सुझाव मिले हैं।'

हालांकि पांडेय ने संभावित निवेशकों के नामों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि विमानन कंपनी के निजीकरण से यह एक मजबूत कंपनी बनेगी और इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को लाभ होगा। पांडेय ने कहा, 'एयर इंडिया भारत के विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और देश को 2024-25 तक 5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी।' (शेष पृष्ठ 7 पर)

नवंबर में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये के पार

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

- पिछले दो महीनों में जीएसटी संग्रह घटने के बाद नवंबर में 1.03 लाख करोड़ रुपये हुई वसूली
- जुलाई 2017 के बाद से आठवां मौका है जब जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है
- विश्लेषकों ने कहा, अक्टूबर में त्योहारी महीना होने की वजह से जीएसटी में इजाफा

त्योहारी मांग और कर चोरी रोकने के उपायों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सुधरकर नवंबर में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। पिछले दो महीने संग्रह में गिरावट आने के बाद नवंबर में वित्त मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह पिछले साल के सितंबर की तुलना में 6 फीसदी बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। अक्टूबर 2019 में 95,380 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह हुआ था। राजस्व में कमी से जूझ रही सरकार के लिए जीएसटी संग्रह में वृद्धि निश्चित तौर पर राहत की खबर है। सरकार ने जीएसटी संग्रह का मासिक लक्ष्य 1.18 लाख करोड़ रुपये तय किया है।

त्योहारी मौसम होने से घरेलू स्तर पर जीएसटी संग्रह 12 फीसदी बढ़ा है जो इस साल सर्वाधिक है। हालांकि आयात से जीएसटी वसूली अब भी ऋणात्मक बनी हुई है। जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद यह आठवां मौका है जब जीएसटी का मासिक संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। इसके साथ ही नवंबर 2019 में सरकार को जीएसटी से अब तक का तीसरा सबसे ज्यादा राजस्व मिला है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि उत्साहजनक है लेकिन केवल एक महीने के आंकड़ों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जजा सकता, खासतौर पर त्योहारी महीने के आंकड़ों से। (शेष पृष्ठ 4 पर)

फिर घटी कारों की बिक्री

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

- अक्टूबर में त्योहरी मांग बढ़ने के बाद नवंबर में फिर घटी कारों की बिक्री
- मारुति की बिक्री में 1.9 फीसदी की कमी
- हुंडई की घरेलू बिक्री में मामूली इजाफा

त्योहारी मौसम की वजह से अक्टूबर में यात्री कारों की बिक्री बढ़ने के बाद नवंबर में एक बार फिर इसमें गिरावट आई है। कंपनियों के आंकड़ों से पता चलता है कि कारों और दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री करीब 8 फीसदी घटी है। थोक बिक्री का मतलब फैक्टरी से देश-विदेश में डीलरों के यहां वाहनों की आपूर्ति से है।

टाटा मोटर्स में यात्री वाहन कारोबार इकाई के अध्यक्ष मयंक पारीक ने कहा, 'त्योहरी मौसम में उत्साहजनक बिक्री के बाद नवंबर में उद्योग में तेज गिरावट आई है। इसके साथ ही वाहन उद्योग बीएस-6 के वाहन लाने की तैयारी में है। खुदरा बिक्री की अपनी रणनीति के अनुरूप हमने अपने नेटवर्क दायरे का और विस्तार किया है।'

उदाहरण के तौर पर देश की प्रमुख वाहन विनिर्माता मारुति सुजूकी इंडिया ने नवंबर में घरेलू बाजार में 1,50,630 कारों की बिक्री की जो नवंबर 2018 की 1,53,539 कारों की बिक्री से 1.9 फीसदी कम है।

प्रवेश स्तर की कारों जैसे ऑल्टो और वैगन आर की बिक्री 26,306 कारों की रही जबकि पिछले साल इस दौरान 29,954 कारों की बिक्री हुई थी। उद्योग के कार्याधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने नवरात्र और धनतेरस की वजह से मांग में थोड़ा सुधार हुआ था, जिसे मांग बढ़ने का पैमाना नहीं माना जा सकता क्योंकि कारों की बिक्री बढ़ाने वाले अधिकतर मुद्दे अब भी पहले की तरह बने हुए हैं। उधर, हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री नवंबर में मामूली बढ़कर 44,600 कारों की रही। (शेष पृष्ठ 2 पर)

नवंबर में फिर घटी कारों की बिक्री

पृष्ठ 1 का शेष

हुंडई मोटर इंडिया के राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख विकास जैन ने कहा, 'घरेलू और निर्यात बाजारों में मांग में सुधार के कारण हुंडई ने नवंबर में 60,500 यूनिट की बिक्री के साथ 7.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। बाजार की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद ग्रैंड आई10, नियोस, वेन्यू, क्रेटा और एलीट आई20 की बिक्री अच्छी रही।'

हालांकि उद्योग को उम्मीद है कि नए साल और शादियों के मौसम के जोर पकड़ने से खरीदारों की धारणा में सकारात्मक बदलाव आएगा जिससे दिसंबर में परिस्थितियां बदल सकती हैं। महिन्द्रा ऐंड महिन्द्रा के बिक्री और विपणन प्रमुख (ऑटोमोटिव डिवीजन) विजय राम नाकड़ा ने कहा, 'त्योहारी मौसम के बाद का महीने वाहन उद्योग के लिए सुस्त रहता है। खासकर यात्री वाहन श्रेणी में उपभोक्ता मांग साल के आखिर में यानी दिसंबर में जोर पकड़ती है। इसलिए हम दिसंबर में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।'

कंपनी की बिक्री में नवंबर में पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी की गिरावट आई है। इस महीने कंपनी ने यात्री और वाणिज्यिक वाहन वर्ग में 41,235 वाहन बेचे जबकि पिछले साल नवंबर में उसने 45,101 वाहन बेचे थे। इस श्रेणी में घरेलू बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी की गिरावट आई जबकि निर्यात 26 फीसदी गिर गया। कृषि उपकरण श्रेणी में भी कंपनी की बिक्री में गिरावट इस बात का संकेत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी सुधार आना शुरू नहीं हुआ है। नवंबर में ट्रैक्टरों की बिक्री में 19 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के कृषि उपकरण सेक्टर के अध्यक्ष राजेश जेजुरीकर ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में ट्रैक्टर की बिक्री में सुधार आएगा।

आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ चंदा कोछड़ की याचिका पर सुनवाई आज

अब होगी कॉरपोरेट गवर्नेंस की परख

देव चटर्जी
मुंबई, 1 नवंबर

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोछड़ ने चूंकि बैंक के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है, ऐसे में संकट के दौरान बैंक के निदेशक मंडल का व्यवहार कानूनी जांच के दायरे में आएगा। निदेशक मंडल ने पिछले साल मार्च में कोछड़ को क्लीन चिट दे दी थी और इस साल जनवरी में अपना रवैया बदलते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

4 अक्टूबर, 2018 को इसी निदेशक मंडल ने कोछड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था जबकि जून में ही बोर्ड जांच का आदेश दे चुका था, जो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की तरफ से किया जाना था। स्टॉक एक्सचेंजों को 4 अक्टूबर को भेजी सूचना में आईसीआईसीआई बैंक ने कहा था कि निदेशक मंडल ने जल्द रिटायरमेंट के कोछड़ के अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बैंक ने यह भी कहा था कि बोर्ड की तरफ से जांच का आदेश इससे अप्रभावित रहेगा।

उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में कोछड़ ने कहा है कि इस साल जनवरी में उनकी बर्खास्तगी कानूनी तौर पर अवैध थी। यह बर्खास्तगी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति बिना की गई, जो सांविधिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है।

कॉरपोरेट वकीलों के मुताबिक, कोछड़ के पूरे मामले में निदेशक मंडल ने लापरवाही बरती और यह बताता है कि बोर्ड का प्रबंधन ठीक नहीं था। पहले निदेशक मंडल ने मार्च में उन्हें क्लीन चिट दे दी जब मीडिया में यह घोटाला सामने आया था। तब उसके चेयरमैन एम के शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंदा का बचाव किया था। 6 जून 2018 को बैंक ने अवकाशप्राप्त न्यायाधीश श्रीकृष्ण को अनियमितता के आरोपों की जांच का काम सौंपा जब उसके बड़े शेयरधारकों ने जवाब मांगा था।

मुंबई के एक वकील ने कहा, कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऐसे गंभीर संकट को संभालने के लिए पहला कदम स्वतंत्र जांच होना चाहिए था।

अगस्त 2018 में अमेरिकी प्रॉक्सी फर्म ग्लास लेविस ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को कोछड़ को चुनने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान की सिफारिश की थी। प्रॉक्सी फर्म ने कोछड़ की तरफ से कानूनी व नियामकीय मसले का सामना करने का हवाला देते हुए यह सुझाव दिया था। इससे कोछड़ पर जल्दी रिटायरमेंट का दबाव और बढ़ा।

एक अन्य वकील ने कहा, शेयरधारक बेहतर गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं और पूरे विवाद में ये चीजें गायब थीं।

इस साल जनवरी में आईसीआईसीआई बोर्ड ने कोछड़ को बर्खास्त कर दिया जब श्रीकृष्ण रिपोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया गया। हालांकि इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई एजेंसियों ने की, लेकिन किसी एजेंसी ने कोछड़ पर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। भारतीय कानून के मुताबिक, किसी अदालत की तरफ से दोषी ठहराए जाने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। वकील ने कहा, तब तक कोछड़ मजबूती से डटी हुई हैं।

चंदा बनाम आईसीआईसीआई बैंक

- गलत तरीके बर्खास्तगी के खिलाफ कोछड़ पहुंचीं उच्च न्यायालय
- 2 दिसंबर को होगी कोछड़ की याचिका पर सुनवाई
- आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने कोछड़ की जांच पर टालमटोल किया
- बोर्ड ने जनवरी में कदम उठाया जब श्रीकृष्ण रिपोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया गया
- अब निदेशक मंडल का व्यवहार आएगा कानूनी जांच के दायरे में

संकटग्रस्त क्षेत्रों का प्रावधान ऐक्सिस ने किया दोगुना

एजेंसियां
मुंबई, 1 दिसंबर

ऐक्सिस बैंक उन क्षेत्रों के कर्ज के लिए नियामकीय अनिवार्यता के मुकाबले दोगुनी रकम अलग रख रहा है, जिसकी पहचान बैंक ने दबाव वाले क्षेत्र के तौर पर की है।

ऐसे क्षेत्रों के फंसे कर्ज के लिए बैंक मानक परिसंपत्ति प्रावधान एक फीसदी बरकरार रख रहा है, जबकि नियामकीय अनिवार्यता 0.40 फीसदी की है। बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीव आनंद ने यह जानकारी दी। अप्रैल से ही बैंक इस राह पर चल रहा है और यह बैंक के खाते पर बढ़ती गैर-निष्पादित आस्तियों पर जताई जा रही चिंता के बीच देखने को मिला। एनपीए के उच्चस्तर और प्रावधान ने पिछले चार साल में ऐक्सिस बैंक समेत ज्यादातर बैंकों के लाभ पर असर डाला है। आनंद ने कहा, उच्च जोखिम के तौर पर पहचाने गए क्षेत्र में हमने मानक प्रावधान बढ़ाकर 100 आधार अंक पर दिया है जबकि अनिवार्यता 40 आधार अंक की है।

अप्रैल 2019 में बैंक ने सबसे पहले खुलासा किया था कि उसने अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराना शुरू किया है, लेकिन वास्तव में अतिरिक्त प्रावधान का वास्तविक स्तर नहीं बताया था या यह भी नहीं बताया था कि यह किन क्षेत्रों के लिए है। यह पूछे जाने पर कि क्या रियल एस्टेट व एनबीएफसी को इस सूची में शामिल किया गया है, आनंद ने किसी क्षेत्र के बारे में बताने से मना कर दिया जिसे उसने दबाव वाले क्षेत्र के तौर पर पहचाना है।

आनंद ने स्पष्ट तौर पर कहा, हमने किसी क्षेत्र की मुश्किलों के कारण उसे उधारी बंद नहीं की है। हर क्षेत्र में हमेशा मजबूत नाम होते हैं, जिनकी रेटिंग बेहतर होती है और उनका कारोबारी मॉडल भी बेहतर होता है।

आनंद ने कहा कि बैंक ने अपने जोखिम आकलन ढांचे को दुरुस्त किया है, जहां लोन जारी होने की मूल जगह को अंडरराइटिंग से अलग किया है और मुख्य क्रेडिट अफसर सीधे मुख्य कार्याधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से प्रोजेक्ट फाइनैंस बंद करने की खबर के बीच आनंद ने संकेत दिया कि ऐक्सिस बैंक भी इसी तरह की रणनीति अपना रहा है।

राहत की मांग पर एक साथ आए सीआईआई, फिक्की

दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर परस्पर विरोधी तर्क-वितर्क के बीच सीआईआई और फिक्की ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र को राहत देने की मांग की है। न्यायालय ने एजीआर पर केंद्र की बात को सही करार देते हुए कंपनियों को आदेश दिया है कि वे उसके आधार पर पुराना सांविधिक बकाया चुकाएं, जो करीब 1.47 लाख करोड़ बनता है। सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने 19 नवंबर को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में राजस्व साझा करने की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार कर इसकी जगह प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा, दूरसंचार क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियों की खराब स्थिति तथा उनके ऊपर सात लाख करोड़ रुपये के अनुमानित भारी-भरकम कर्ज से न सिर्फ इन कंपनियों के अस्तित्व के लिए चुनौती उपस्थित हो रही है। फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने भी इसे लेकर वित्त मंत्री को 27 नवंबर को पत्र लिखा था। *भाषा*

वोडा-आइडिया ने याचिका में बताए वित्तीय हालात

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

हालिया एजीआर आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपनी समीक्षा याचिका में वोडाफोन आइडिया ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का असर इतना भयावह है कि हमारी जैसी दूरसंचार कंपनी वित्तीय दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई हैं और कंपनी की हैसियत तेजी से घट रही है।

अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से कंपनी ने कहा है कि उसने कोई अनुचित मुनाफा नहीं कमाया है या राजस्व साझेदारी व्यवस्था का फायदा उठाया है। कंपनी ने कहा कि उसके प्रवर्तकों (वोडाफोन, आदित्य बिड़ला समूह) और शेयरधारकों ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है, जिसमें से 1.65 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसके बावजूद कंपनी अभी भी दबाव का सामना कर रही है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि शेयरधारकों समेत कंपनी में कुल निवेश, बैंकों से उधारी और टली हुई भुगतान का दायित्व अभी 3.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

कंपनी ने कहा है कि पिछले 10 साल में उसका संचयी परिचालन नुकसान 55,175 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें वोडाफोन के लाइसेंस वाली इकाइयों का परिचालन शामिल है, जिसका विलय कंपनी में वित्त वर्ष 2018-19 में हुआ। इस नुकसान में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पड़ने वाला असर शामिल नहीं है, जो उनके आकलन के मुताबिक मौजूदा विनिमय दर पर 44,150 करोड़ रुपये यानी 6.3 अरब डॉलर है।

वोडाफोन आइडिया ने हाल में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की है, जिसके जरिए 1.47 लाख करोड़ रुपये सभी दूरसंचार कंपनियों को एजीआर व स्पेक्ट्रम यूजेज शुल्क के तौर पर संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग को चुकाने हैं। भारती एयरटेल, टेलिनॉर और वीजियोकॉन ने भी समीक्षा याचिका दाखिल की है। वोडाफोन आइडिया का बकाया सभी दूरसंचार कंपनियों में सबसे ज्यादा है।

याचिका में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वह वित्तीय दिवालिया होने के कगार पर हो सकती है। वोडाफोन पीएलसी के सीईओ निक रीड ने कहा था कि भारतीय संयुक्त उद्यम परिसमापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया। अपनी याचिका में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह अब तक सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क के तौर पर 59,467 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति

- वोडाफोन आइडिया ने 2018-19 में 14,056 करोड़ रुपये का परिचालन नुकसान दर्ज किया
- जनवरी-मार्च 2019 में नुकसान 4,927 करोड़ रुपये था
- अप्रैल-जून 2019 में नुकसान 5,038 करोड़ रुपये रहा
- जुलाई-सितंबर 2019 में कंपनी का नुकसान 49,727 करोड़ रुपये रहा

तुर्की से प्याज आयात का नया ठेका जारी

सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत तुर्की से 11 हजार टन प्याज आयात करने का नया ठेका दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। यह एमएमटीसी द्वारा प्याज के आयात के लिए दिया गया दूसरा ठेका है। कंपनी पहले ही मिस्र से 6,090 टन प्याज का आयात का ऑर्डर दे चुकी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 1.2 लाख टन प्याज आयात करने की मंजूरी दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाने के बाद इसकी आपूर्ति बढाने के उद्येश्य से सरकार ने इसके आयात सहित कई कदम उठाए हैं। प्याज निर्यात पर रोक लगाई जा चुकी है तथा थोक व खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज के भंडार की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार एमएमटीसी ने तुर्की से 11 हजार टन प्याज मंगाने का करार किया है। इसके तहत अगले साल जनवरी से प्याज की खेप मिलने की शुरुआत की उम्मीद है। मिस्र से 6,090 टन प्याज इस महीने के दूसरे सप्ताह में मुंबई के जवाहर नेहरू पोर्ट टर्मिनल पर पहुंच सकता है। प्याज के भाव पर नियंत्रण के लिए गृहमंत्री अमित शाह की अगुआई में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। इसमें वित्त मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, कृषि मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री भी रखे गए हैं। *भाषा*

अगले साल धीमी रहेगी सोने की रफ्तार!

नैटिक्सिस ने वर्ष 2020 के दैरान सोने के दामों का परिदृश्य नरम रहने की जताई संभावना

राजेश भयानी
मुंबई, 1 दिसंबर

सोने के दामों में लगातार गिरावट शुरू होने के साथ ही इसकी तेजी की राह में पहली बाधा उत्पन्न हो गई है। नैटिक्सिस ने अगले साल के परिदृश्य में गिरावट जताई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में सोने के अंतरराष्ट्रीय दामों में 3.72 प्रतिशत की गिरावट आई है जो नवंबर 2016 के बाद से किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। तब एक महीने में सोने के दामों में 8.14 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

अमेरिका-चीन व्यापार को लेकर सहज माहौल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास वृद्धि के संकेतों के बाद सोने के दाम तकरीबन 100 डॉलर प्रति औंस गिरकर फिलहाल 1,456 डॉलर प्रति औंस हो चुके हैं। नैटिक्सिस के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक बर्नार्ड डहडाह ने कहा कि वर्ष 2020 के लिए दामों का हमारा पूर्वानुमान संशोधित करके औसतन 1,370 डॉलर प्रति औंस कर दिया गया है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संबंध में और अधिक सकारात्मक परिदृश्य तथा हमारी इस उम्मीद को प्रतिबिंबित करता है कि फेड दर में कटौती का चक्र पूरा हो चुका है।

वर्ष 2019 में अब तक सोने के दाम औसतन 1,385.13 डॉलर के स्तर पर रहे हैं और अगले साल का औसत इससे भी कम नजर आ रहा है।

वर्ष 2018 में औसत दाम 1,264 डॉलर प्रति औंस थे। हालांकि वर्ष 2019 में तेजी का रुख मुख्य रूप से दूसरी छमाही में था और जुलाई से नवंबर के बीच दाम औसतन 1,477 डॉलर रहे हैं जिसका अर्थ यह है कि अगर नैटिक्सिस का पूर्वानुमान सच होता है तो अगले साल दाम तेजी से गिरेंगे।

कंपनी ने यह भी कहा है कि दो प्रमुख उपभोक्ता देशों – चीन और भारत की मांग में तेज गिरावट और तीसरी तिमाही में अमेरिकी जीडीपी उम्मीद से बेहतर रहने की वजह से सोने का आकर्षण कम रहेगा। इससे पहले सीआईटीआई ने भी कहा था कि विशेष रूप से अमेरिका-चीन के मद्देनजर वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार के बाद निकट अवधि में सोना नरम रहने के आसार हैं।

कॉमट्रेंडज रिसर्च के निदेशक टी गणशेखर ने कहा कि व्यापारिक वार्ता और दिसंबर के मध्य में फेड की बैठक के संबंध में आ रही खबरों के कारण निकट अव
में कुछ दबाव रह सकता है जिससे
चलकर वर्ष 2020 में दामों क
निर्धारित होगी। हालांकि मध्य
संबंध में उनका रुख इतना
उन्होंने कहा कि शेयर
फेड के रुख में संभव
कमजोर डॉलर के
दूसरी छमाही में
मदद मिल स
इससे

गिरावट की आहट

- नवंबर में सोने के अंतरराष्ट्रीय दामों में आई है 3.72 प्रतिशत की गिरावट
- नवंबर 2016 के बाद से किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है यह
- नैटिक्सिस ने वर्ष 2020 के लिए दामों का पूर्वानुमान संशोधित करके किया औसतन 1,370 डॉलर प्रति औंस
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अधिक सकार
- वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार के सोना नरम रहने के आसार
- शेयर बाजारों में तेजी, फेड के कमजोर डॉलर से दूसरी छ सकती है काफी मदद

'तर' मॉनसून से उत्पादन होगा

भारत का सालाना गेहूं उत्पादन वर्ष 2020 में उछलकर लगातार दूसर बार रिकॉर्ड स्तर तक जा सकत 25 सालों में सबसे अधिक वाले मॉनसून के कारण सर्दियों में बोई जा फसल के अंतर्गत करने में मदद इससे उपज उद्योग के यह क

कम आपूर्ति, मांग वृद्धि से अनाज में तेजी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 1 दिसंबर

सब्जियों के बाद अनाज के दामों में तेजी आनी शुरू हो गई है। उपभोग के स्वरूप में हो रहे बदलाव के कारण मांग बढ़ने और अत्यधिक बारिश की वजह से फसल को पहुंचे नुकसान के बाद खरीफ उत्पादन में गिरावट आने की संभावना से ऐसा हो रहा है। हालांकि सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास बड़ी मात्रा में उपलब्ध स्टॉक की वजह से चावल और गेहूं समेत प्रमुख अनाजों में कुछ ही तेजी आई है, लेकिन इस साल कम पैदावार के पूर्वानुमान के कारण पिछले एक महीने के दौरान मोटा अनाज 16 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है।

उदाहरण के लिए बेंचमार्क केकड़ी (राजस्थान) मंडी में ज्वार के दाम हाल ही में 16 प्रतिशत उछलकर 1,890 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं, जबकि नवंबर की शुरुआत में दाम 1,630 रुपये प्रति क्विंटल थे। इसी तरह बाजरे और रागी के दाम भी नवंबर में क्रमश: 3.3 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

इसके अलावा पिछोर (मध्य प्रदेश) में गेहूं के दाम हल्के-से बढ़कर 1,990 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं, जबकि पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में चावल का भाव 3.1 प्रतिशत तक कम होकर फिलहाल 2,520 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर है। सब्जियों और मोटे अनाज सहित लगभग सभी खाद्य पदार्थों के दामों में काफी इजाफा होने की वजह से उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से रसोई के पूरे बजट पर असर झेलना पड़ेगा जो उनकी बचत बिगाड़ने के लिए काफी रहेगा।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण इस साल मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता व्यवहार का रुख स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ओर रहने से पिछले कुछेक सालों के दौरान इनकी मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। आपूर्ति में कमी और मांग बढ़ने के कारण मोटे अनाजों के दामों में मजबूती आ रही है। मोटे अनाज के दाम मुख्य रूप से मांग-आपूर्ति के सिद्धांत से संचालित होते हैं।

प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल क्षति के बाद आपूर्ति घटने से मोटे अनाजों के अलावा सब्जियों के दाम भी पिछले छह से आठ सप्ताह के दौरान दोगुने हो चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई कृषि प्रधान राज्य पौधों के अंकुरण के दौरान बाढ़ की चपेट में थे जिसके परिणामस्वरूप कृषि पैदावार में कमी आई, नुकसान हुआ और खरीफ की बुआई वाली फसलों की कटाई में देरी हुई। इन सभी कारणों से त्योहारी सत्र के दौरान मोटे अनाजों और सब्जियों आदि की आपूर्ति में बाधा आई और यह बाधा आगे भी जारी रही।

तकनीक और सेवा प्रदाता फास्टैग के लिए तैयार

नेहा अलावधी, पीरजादा अबरार और करण चौधरी
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 1 दिसंबर

देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रौद्य कंपनियां और सेवा प्रदाता पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि फास्टैग लागू करने का वक्त परिवहन मंत्रालय ने 2 सप्ताह बढ़ा दिया है, जो रविवार 1 दिसंबर से लागू होने वाली थी।

फास्टैग एक उपकरण है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंडिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक होती है। इस व्यवस्था के तहत फास्टैग लगे वाहन जब टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो सीधे टोल भुगतान हो जाता है। फास्टैग (आरएफआईडी टैग) वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है और इससे ग्राहकों को यह सुविधा होती है कि वे टोल का भुगतान सीधे अपने बैंक खाते से कर सकते हैं, जिससे फास्टैग जुड़ा हुआ होता है।

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान की व्यवस्था लागू की जा रही है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का संयुक्त प्रयास है।

एनईटीसी देशव्यापी अंतरसंचालित टोल भुगतान सॉल्यूशंस मुहैया कराता है, जिसमें निपटान के लिए क्लियरिंग हाउस सर्विसेज और विवाद प्रबंधन शामिल है। दरअसल ग्राहक सामान्य भुगतान प्रक्रिया से देश के किसी भी टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान कर सकेंगे। फास्टैग खाता सीधे ग्राहक के बैंक खाते से जुड़ा होगा और यह रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान में सक्षम होगा। इसकी वजह से टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं होगा और इससे समय बचेगा।

इस समय फास्टैग को 20 से ज्यादा बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। यह देश के 560 से ज्यादा टोल प्लाजा पर सक्रिय है। फास्टैग की वैधता इसे खरीदने के वक्त से लेकर 5 साल तक की है और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन रिचार्ज सुविधा और रिचार्ज व कम बैलेंस पर एसएमएस अलर्ट आदि की सुविधा है।

आंकड़ों में फास्टैग

- नवंबर में फास्टैग के माध्यम से औसतन रोजाना **11.2** लाख लेन देन हुए
- नवंबर में रोजाना का औसत संग्रह **19.5** करोड़ रुपये
- कुल **70** लाख से ज्यादा फास्टैग जारी हुए
- प्रतिदिन जारी होने वाले आंकड़ों में 26 नवंबर को **1.35** लाख फास्टैग जारी
- **560** से ज्यादा टोल प्लाजा पर स्वीकार होते हैं फास्टैग

कुछ टेक कंपनियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में फास्टैग की बिक्री में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सेवा प्रदाताओं ने अपने बैकएंड टेक को दुरुस्त किया है, जिससे टोल बूथ पर फास्टैग के इस्तेमाल में कोई दिक्कत न आए।

पेटीएम जैसी फिनटेक दिग्गजों ने कहा है कि वे रोजाना इतने फास्टैग की बिक्री कर रही हैं, जितना बैंक कुल मिलाकर कर रहे हैं। एनईटीसी कार्यक्रम के हिस्सा के रूप में पेटीएम पेमेंट बैंक ने एनएचएआई से समझौता किया है, जिससे एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा से वाहन बाधारहित तरीके से गुजर सकें।

कंपनी ने कहा, 'इस समय हम भारत में सबसे ज्यादा फास्टैग जारी करने वाले हैं और इस साल सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी भी अन्य बैंक की तुलना में हमने ज्यादा फास्टैग जारी किए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक भारत में 110 से ज्यादा टोल प्लाजा का अधिग्रहण बैंकों से किया है। हम आने वाले वर्षों में 100 टोल प्लाजा के अधिग्रहण करने की योजना बना रहे हैं।'

पेटीएम फास्टैग यात्री वाहनों के लिए पूरी तरह मुफ्त है और टैग जारी करने की 100 रुपये लागत माफ कर दी गई है। ग्राहकों को सिर्फ 400 रुपये भुगतान करने पड़ते हैं, जिसमें 250 रुपये सिक्योरिटी जमा है, जबकि 150 रुपये न्यूनतम जमा बरकरार रखना होता है।

आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को किसी भी अफरातफरी से बचने के लिए कंपनी ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है और फास्टैग लगाने की घोषणा के बाद पर्याप्त वक्त दिया गया है।

अपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फास्टैग बेचने वाले प्लेटफॉर्म इसमें बेहतर कारोबार देख रहे हैं। एमेजॉन इंडिया के मुताबिक फास्टैग की बिक्री बढ़ी है।

ई कॉमर्स दिग्गज ने कहा, 'ग्राहक फास्टैग लेने में सहूलियत देख रहे हैं और उसे खरीदने के मौजूदा साधनों में टोल प्लाजा से खरीदने से लेकर साझेदार बैंक की शाखाओं या वेबसाइट का विकल्प मौजूद है। एमेजॉन डॉट इन अपने व्यापक लॉजिस्टिक्स और डिलिवरी नेटवर्क के माध्यम से इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में सक्षम है। नवंबर 2019 के पहले सालाना आधार पर फास्टैग की बिक्री 30 गुना बढ़ी है। सरकार द्वारा 1 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा के बाद पहले के महीने की तुलना में बिक्री ढाई गुना बढ़ गई थी।'

लॉजिस्कि टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक ने कहा कि वाणिज्यिक ई-टोलिंग में उसकी बाजार हिस्सेदारी 25 प्रतिसत है। बेंगलूरु की फर्म ने देश के सभी ट्रक मालिकों को मुफ्त फास्टैग देने की पेशकश की है। ट्रक मालिक ब्लैकबक के बॉस ऐप के माध्यम से फास्टैग मंगा सकते हैं। यह डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म ट्रक के बेड़े चलाने वाले मालिकों के लिए विकसित किया गया है और 31 दिसंबर 2019 तक फास्टैग उनके घर तक मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से 30 लाख से ज्यादा ट्रकों को मदद मिलेगी, जिन्हें फास्टैग अनुपालन करना है।

ब्लैकबक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी राजेश याबाजी ने कहा, 'हमारे प्लेटफॉर्म से पहले ही भारत के कुल ट्रकों में से 50 प्रतिशत जुड़े हुए हैं और फास्टैग एट डोरस्टेप जैसी पहल से हम आगे सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग एजेंडे को समर्थन कर रहे हैं। इससे टोल वसूली का वक्त कम होगा और इससे भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में अहम बदलाव आएगा।'

एफएमसीजी की साझेदारी से कृषि को मजबूत करने की कवायद

बीएस संवाददाता
जालंधर, 1 दिसंबर

पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र को किसानों की प्रगति का एक सशक्त जरिया बनाने के लिए इसके आधुनिकीकरण पर जोर देने का निर्णय लिया है। राज्य में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट, 2019 का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार विश्व की अग्रणी एफएमसीजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर कृषि क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास करेगी।।

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र पराली से निपटने के उपाय खोज रहा है। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) इस क्षेत्र को अधिक समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे रही है।

इस क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देने और नई पहल करने में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन खासा मददगार होगा।

कृषि क्षेत्र मजबूत होने से किसानों की आय में भी इजाफा होगा। इस सम्मेलन के जरिये कृषि पर केंद्रित स्टार्टअप कंपनियों के लिए समर्थन जुटाने में भी मदद लेगी। इन दिनों स्टार्टअप की संख्या में खासी तेजी आई है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन्होंने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की है।

कृषि क्षेत्र से संबद्ध कंपनियों जैसे आईटीसी, गोदरेज टायसन, हरियाली सीड्स, इफको और स्पेन की कॉन्गलेडोस डे नवारा ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। पंजाब औद्योगिक एवं कारोबार विकास नीति, 2017 में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर खासा जोर दिया गया है और इनके लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार का दावा है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। राज्य के फाजिल्का, लुधियाना और फगवाड़ा में तीन मेगा फूड पार्क बनाए गए हैं।

जीएसटी 1 लाख करोड़ रु. के पार

पृष्ठ 1 का शेष

प्रतीक जैन कहा, 'हमें यह देखना होगा कि रुझान कैसा है। सरकार ने अनुपालन को सरल बनाने के लिए सही दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अगले साल से ई-इनवॉयसिंग भी लागू करने जा रही है। इससे जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे इजाफा हो सकता है। हालांकि यह अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा।'

नवंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 19,592 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर में 17,582 करोड़ रुपये था। राज्य जीएसटी संग्रह 27,144 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 49,028 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले महीने 46,517 करोड़ रुपये रहा था।

टैक्समैन के डीजीएम विशाल रहेजा ने कहा, 'अक्टूबर में त्योहारी महीना होने की वजह से राजस्व संग्रह बढ़ा है। इसके अलावा नए प्रावधान के तहत जीएसटीआर-2ए में अधिकतम आईटीसी के तौर पर केवल बिल के 120 फीसदी क्रेडिट की ही अनुमति दी गई है, जिससे संग्रह में इजाफा हुआ है।'

> नवंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 19,592 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर में 17,582 करोड़ रुपये था। राज्य जीएसटी संग्रह 27,144 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 49,028 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले महीने 46,517 करोड़ रुपये रहा था

राजस्व चोरी रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था कि है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित बिलों को अपलोड नहीं करने की स्थिति में इनपुट कर क्रेडिट को 20 फीसदी तक सीमित करने का निर्णय किया है ।पिछले महीनों में उम्मीद से कम कर संग्रह से सरकार को राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई करने का भी दबाव बढ़ रहा है। मुआवजा उपकर संग्रह नवंबर में 7,727 करोड़ रुपये रहा जबकि मासिक आधार पर राज्यों को करीब 13,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो रहा है। अगस्त और सितंबर में मुआवजा भुगतान में देरी की वजह से भी राज्य सरकार केंद्र पर दबाव बना रही है।

चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपये कम कर राजस्व मिलने का अंदेशा है। सरकार ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के उपाय तलाशने के लिए अक्टूबर में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों वाली 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2020 में केंद्रीय जीएसटी में 16 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आगामी बजट में कम किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट में 6.1 लाख करोड़ केंद्रीय जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा गया था जिसे बजट में कम कर 5.26 लाख करोड़ रुपये किया जा चुका है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एमएस मणि ने कहा कि त्याहारी महीने में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है, उम्मीद है कि आने वाले महीनों में भी यह रुझान बना रह सकता है। नवंबर में कुल 77.83 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया गया।

महंगाई दर से नीचे आ सकती है ब्याज दर

अनूप रॉय
मुंबई, 1 दिसंबर

- रीपो दर में **15** से **25** आधार अंक कटौती की उम्मीद जता रहे अर्थशास्त्री
- अगर महंगाई दर बढ़कर **5** प्रतिशत से ऊपर जाती है तो ब्याज दर हो सकती है महंगाई से नीचे
- फरवरी से रिजर्व बैंक कर चुका है रीपो रेट में **135** आधार अंक की कटौती

सितंबर तिमाही में वृद्धि दर 6 साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर पहुंचने से अब मौद्रिक नीति समिति की 5 दिसंबर को होने वाली बैठक में नीतिगत दरों में कटौती करीब निश्चित है। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त होने से बड़े मौद्रिक और राजकोषीय फैसलों की जरूरत महसूस की जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अर्थशास्त्रियों से रायशुमारी में यह सामने आया है।

दरों में कटौती 15 आधार अंक की हो सकती है, जिससे नीतिगत रीपो दर मानक 5 प्रतिशत पर आ सकती है। या इसमें 24 आधार अंक की भी कटौती हो सकती है। लेकिन केंद्रीय बैंक को ऐसी स्थिति में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सब्जियों के दाम बढ़ने से महंगाई दर नवंबर में 5 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। नीतिगत दर 5 प्रतिशत या इससे नीचे रहने का मतलब यह है कि ब्याज दर महंगाई दर से नीचे रह सकती है।

गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) फरवरी से नीतिगत दरों में 5 बार यानी कुल मिलाकर 135 आधार अंक की कटौती कर चुकी है। साथ ही समावेशी स्थिति बनाए रखने का वादा किया है, क्योंकि वृद्धि बहाल करने के लिए यह जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि महंगाई दर लक्ष्य के मुताबिक बनी रहे। लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कटौती का असर नहीं पड़ा है। मांग की स्थिति बहुत खराब हो गई है।

हालांकि बाजार दरों पर दरों में कटौती पर पूरा असर रहता है, लेकिन कंपनियां जरूरी नहीं है कि उधारी लेने का मन बना रही हों। कंपयिनां इस समय खपत मांग और निवेश में कमी का सामना कर रही हैं। एसपी जैन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट ऐंड रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण ने बिजनेस स्टैंडर्ड के अपने कॉलम में लिखा है कि घरेलू बचत सरकार के संयुक्त राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता।

एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'रिजर्व बैंक अकेले बड़ी तेजी नहीं ला सकता। हमारे यहां अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि महंगाई दर रीपो रेट से ज्यादा है और वास्तविक ब्याज दर शून्य या नकारात्मक में जा सकती है।'

लेकिन दरों में भारी कटौती से कुछ गहरी बुनियादी समस्याएं आ सकती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा, 'हाल के जीडीपी आंकड़ों में निजी अंतिम खपत व्यय में तेजी से कर्ज वित्तपोषित खपत की ओर संकेत हो सकता है। साथ ही सांकेतिक जीडीपी वृद्धि ब्याज दर से नीचे रहना कर्ज बढ़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे में हमें सक्रिय राजकोषीय नीति की जरूरत है।'

ऐक्सिस बैंक के मुख्य आर्थशास्त्री सौगात भट्टाचार्य को उम्मीद है कि आने वाली उपभोक्ता मूल्य आधारित (सीपीआई) महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रहेगी, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कटौती करेगा।

इंडसइंड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरव कपूर ने कहा, 'वृद्धि क्षमता से कम है ऐसे में मौद्रिक नीति समिति चक्रीय मंदी से निपटने पर ध्यान केंद्रित रखेगी। प्रमुख महंगाई दर लक्ष्य को पार कर सकता है और इसके बढ़े रहने की उम्मीद है। यह खासकर यह अल्पकालिक मुद्रास्फीतिक दबावों की वजह से होगा।'

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पण ने कहा, 'नकारात्मक आउटपुट की खाईं बढ़ना जारी है। प्रमुख महंगाई गिर रही है और आंकड़े कोई बेहतर संकेत नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से खाद्य कीमतों की उपेक्षा की जा सकती है।'

एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा कि अभी 25 आधार अंक की दरों में कटौती की संभावना बन रही है क्योंकि आगे और कार्रवाई जरूरी है।

आईसीआईसीआई बैंक के वैश्विक बाजार के प्रमुख बी प्रसन्ना ने कहा, 'कम वृद्धि और सकल मांग में कमी से और नीतिगत नरमी की संभावना बन रही है।'

एलऐंडटी फाइनैंस ग्रुप में मुख्य अर्थशास्त्री रूपा रेगे नित्सुरे ने कहा कि आदर्श रूप में देखें तो एमपीसी को अब विराम देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हालांकि रीपो रेट में 15 आधार अंक की कटौती हो सकती है।' नित्सुरे ने कहा कि एमपीसी को चालू वित्त वर्ष के शेष समय में भी नीतिगत दर स्थिर रखना चाहिए, लेकिन वे चौथी तिमाही में एक बार और कटौती कर सकते हैं।

ठप हो जाएगा शीर्ष कारोबारी न्यायालय का काम

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कारोबारी विवाद का निपटारा करने वाला शीर्ष न्यायालय पहली बार ठप होने जा रहा है। भारत और 116 अन्य देश अमेरिका को नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का विरोध न करने को लेकर समझाने में विफल रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने पिछले सप्ताह एक बैठक में अंतिम कवायद की कि 2 साल से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाए, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे। अब वैश्विक मंच पर कारोबारी विवादों के निपटान के शीर्ष न्यायालय का काम 10 दिसंबर से रुक जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि भारत जिन अहम कारोबारी विवादों की लड़ाई लड़ रहा है, अधर में लटक जाएंगे। भारत जिन विवादों को डब्ल्यूटीओ ले गया है, उनमें ज्यादातर निवेश संवर्धन योजनाओं को खत्म करने का मामला शामिल है। डब्ल्यूटीओ के जिनेवा स्थित मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ज्यादातर देशों, जिसमें भारत के नेतृत्व वाला बड़ा गठजोड़ शामिल है, ने अमेरिका से कहा कि वह अपना रुख बदले। यहां तक कि 22 नवंबर की बैठक के बाद भी नई दिल्ली ने डब्ल्यूटीओ की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर अमेरिका से इस मसले पर बात की, लेकिन उन्हें बहुत सीमित सफलता मिली।'

डीएसबी सभी 163 डब्ल्यूटीओ देशों के साथ मिलकर बना है, जो 7 सदस्यों वाले अपीली निकाय का चयन करहा है। यह निकाय कारोबारी विवादों के निपटान के लिए शीर्ष निकाय है। अपील निकाय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल होता है, जिसका एक बार नवीकरण हो सकता है। 10 दिसंबर को अपीली निकाय के मौजूदा 3 सदस्यों में से 2 सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिनमें भारत के उजय सिंह भाटिया और अमेरिका के थॉमस आर ग्राहम शामिल हैं।

वैश्विक कारोबार पर नियंत्रण की लड़ाई

- 7 न्यायाधीश वाला डब्ल्यूटीओ का अपील निकाय कारोबारी विवाद के समाधान के लिए शीर्ष न्यायालय
- उनके नियम डब्ल्यूटीओ में शामिल 163 अर्थवव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं
- ज्यादा लागत और खराब प्रदर्शन का हवाला देकरक अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति का विरोध किया
- लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ट्रंप के शुल्कों के बाद अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ का कद घटा दिया
- आखिरी 3 जजों में से 2 जज 10 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिससे यह निकाय ठप हो जाएगा

अमेरिका की मांग

अपील निकाय में न्यायाधीशों की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गया है क्योंकि इसे देशों के बीच कारोबारी विवाद में पंचाट के रूप में काम सौंपा गया है। अधिकारियों ने कहा कि अभी स्थिति यह है कि मामलों की सुनवाई में एक साल से ज्यादा वक्त लगता है।

बहुपक्षीय कारोबारी व्यवस्था में विवाद के निपटान में डब्ल्यूटीओ अहम है और संगठन की वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता में योगतान को लेकर अहम भूमिका है। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक कारोबार पर डब्ल्यूटीओ के बढ़ते नियंत्रण का विरोध किया और इस निकाय को पीछे करते हुए अमेरिका ने चीन सहित अपने कारोबारी साझेदारों पर एकतरफा शुल्क लगाने जैसे कदम उठाए। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर ने बार बार डब्ल्यूटीओ के खिलाफ आवाज उठाई और कहा किवह अमेरिका के साथ गलत कर रहा है. दिलचस्प है कि लाइटहाइजर को 16 साल पहले अपीली निकाय में न्यायधीश के रूप में नामित किया गया था। बहरहाल वह कन्फर्म नहीं हो सके क्योंकि उसके लिए हर देश का एकमत समर्थन जरूरी होता है।

अब अमेरिका यह तर्क दे रहा है कि अपील निकाय के न्याधीशों को बहुत ज्यादा भुगतान दिया जाता है और उस भुगतान का बहुत मामूली औचित्य है। अमेरिका ने यह भी धमकी दी कि वह इस संगठन को मिलने वाला अपना बजट समर्थन रोक देगा।

आगे की चुनौतियां

डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय ने 31 अक्टूबर को यह कहा था कि भारत के ज्यादातर निर्यात संवर्धन योजनाएं अवैध हैं और आदेश दिया था कि अगले 4 महीनों में इन्हें बंद किया जाए। उसने यह भी कहा था कि एसईजेड योजनाएं भी अगले 6 महीने में बंद की जानी चाहिए। निर्यात केंद्रित इकाइयों (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईओटी), बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) योजना, पूंजीगत वस्तुओं की निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना और भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस) को बंद करने के आदेश दिए गए थे। सरकार ने जहां इस नियमन के खिलाफ अपील दायर की थी, वहीं सरकार ने पहले ही मौजूदा योजनाओं में बदलाव शुरू कर दिया।

बीएस सूडोकू 3601 | परिणाम संख्या 3600

		1			8			9
			1	9	3	4		
9	4			6				
	2	3						1
		4				5		
8						7	4	
				1			7	2
		9	8	7	6			
4			5			9		

3	2	6	7	9	8	1	5	4
1	4	7	3	5	6	2	8	9
9	5	8	4	2	1	6	7	3
4	6	9	5	3	2	8	1	7
5	1	3	8	7	9	4	6	2
7	8	2	6	1	4	3	9	5
2	3	1	9	8	5	7	4	6
6	7	5	1	4	3	9	2	8
8	9	4	2	6	7	5	3	1

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान
★ ★ ☆ ☆ ☆

केंद्र से धन के इंतजार में आंध्र, पीपीए पर नहीं झुकेगा

श्रेया जय
नई दिल्ली, 1 दिसंबर

आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा है कि वह बिजली परियोजनाओं का बकाया भुगतान तभी कर पाएगी, जब केंद्र सरकार उसे धन मुहैया कराए। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं रद्द करने के मसले पर लड़ाई खत्म करने से भी इनकार कर दिया है।

इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने एक बैठक में कहा था कि राज्य को उन बिजली परियोजनाओं के बकाये का भुगतान करना चाहिए, जिन्होंने बिजली आपूर्ति की है। पिछले 16-18 महीनों के दौरान अक्षय और ताप बिजली परियोजनाओं का बकाया 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। 7 नवंबर को हुई बैठक में केंदर सरकार के प्रतिनिधि ने कहा था, 'आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति के समाधान के लिए आकर्षक दर पर कर्ज मुहैया कराने की कवायद की जा रही है, जो एपी के जोखिम के स्तर की तुलना में कम होगी। यह धन आरईसी, पीएफसी और आईआरईडीए के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे राज्य बिजली खरीद के बकाये का भुगतान कर सके।'

राज्य सरकार ने गुरुवार को बकाये के भुगतान के बारे में चल रहे मामले में यही दोहराया और कहा कि राज्य को जब तक पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तब तक लंबित और भविष्य के बिल के भुगतान की समस्या हल नहीं हो पाएगी। आंध्र प्रदेश के बिजली, वन और विज्ञान मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास ने ई मेल से भेजे बयान में कहा है, 'आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सब्सिडी युक्त कर्ज देने को कहा है, जिससे इन बकायों का भुगतान किया जा सके और यह अनुरोध अभी विचाराधीन है।'

राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्षय ऊर्जा ठेकों को रद्द करने के राज्य के फैसले पर कोई समझौता करने को सहमत नहीं है। गलत बोली और उच्च दरों का हवाला देते हुए ये ठेके इस साल जुलाई में रद्द कर दिए गए थे।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'केंद्र सरकार ने राज्य को महज यह सुझाव दिया है कि बिजली खरीद सौदों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन राज्य अभी भी अन्य मसलों पर कानूनी लड़ाई खत्म करने को सहमत नहीं है।'

वाईएसआर कांग्रेस ने जुलाई में आंध्र प्रदेश सरकार का कामकाज संभाला था। सरकार ने सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के शुल्क की 'समीक्षा, बातचीत और उसे कम करने' के लिए एक उच्च स्तरीय वार्ता समिति (एचएलएनसी) का गठन किया था। यह समीक्षा उन परियोजनाओं की होनी थी, जिन्हें पिछली आंध्र सरकार ने आवंटित की थी। इसके गठन की वजह राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति बताया गया। कंपनियों ने इस फैसले का विरोध किया और राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा खरीद बंद कर दी।

राज्य के अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के डेवलपर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया। 24 सितंबर के एक आदेश में न्यायालय ने एचएलएनसी भंग कर दिया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीद रोक रखी है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 245

सही मिश्रण जरूरी

पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए एथनॉल की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच भारी अंतर को देखते हुए इसमें दो राय नहीं कि इसका उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। परंतु सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रयास कर रही है वे पर्याप्त नहीं प्रतीत होते। इनमें सबसे बहसतलब है एथनॉल निर्माताओं (अधिकांशतया चीनी मिल मालिक जो इसे राब से बनाते हैं) द्वारा गन्ने के रस को सीधे अल्कोहल में बदलना।

इसके अलावा वे अधिशेष चीनी और खाद्यान्न मसलन गेहूं, चावल और मक्के को भी इसके लिए प्रयोग में लाते हैं। इतना ही नहीं सरकार ने इन कच्चे मालों के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में इनसे बनने वाले एथनॉल की अपेक्षाकृत ऊंची कीमत तय की है।

ऐसे में किसान गन्ने की खेती और चीनी मिलें गन्ने की खरीद, चीनी बनाने के बजाय इस जैव ईंधन के लिए करेंगी। चूंकि गन्ना, गेहूं और चावल के उत्पादन में खूब पानी लगता है इसलिए कहा जा सकता है कि जैव ईंधन उत्पादन में इनका इस्तेमाल पर्यावरण के लिए किसी त्रासदी को आमंत्रण देने के समान है। इनके उत्पादन में लगने वाले पानी की लागत को केवल आर्थिक संदर्भ में नहीं आंका जा सकता। इसकी सामाजिक कीमत, पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से होने वाली आर्थिक बचत से कहीं अधिक हो सकती है।

इतना ही नहीं भारत जैसे देश में जहां बुनियादी ढांचे, उद्योग धंधों और अन्य उद्देश्यों के लिए भी जमीन मुश्किल से मिलती है वहां जैव ईंधन फसल के उत्पादन में इसका इस्तेमाल समझदारी भरा नहीं होगा।

जहां तक खाद्यान्न की बात है, फिलहाल ऐसा लग सकता है कि अधिशेष अन्न को आसानी से जैव ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन देश में व्याप्त कुपोषण और भूख को देखते हुए इसे उचित ठहराना मुश्किल होगा। हकीकत में कई भूसंपदा समृद्ध और औद्योगिक देश, जो गैसोलीन में फसल से बनने वाला जैव ईंधन मिलाते हैं, वे भी अपनी नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि इससे फसल बुआई के तरीके बदल गए हैं और खाद्यान्न कीमतें बढ़ी हैं। जैव ईंधन वाली फसल उगाने के लिए वनों की कटाई की सलाह को भी पर्यावरणविद चुनौती दे रहे हैं। गौरतलब है कि ब्राजील तथा कुछ अन्य देश ऐसा कर रहे हैं।

एक अन्य बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह यह कि भारत में गन्ने तथा खाद्यान्न से इतर तरीकों से भी एथनॉल तैयार करने की काफी संभावना मौजूद है जिसका पूरा दोहन होना अभी बाकी है। वर्ष 2009 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जिसे 2018 में संशोधित किया गया, वहां ग्रामीण और शहरी कचरे, सेलूलोसी और लिंगो सेलुलोसी बायोमास (कृषि के शुष्क पदार्थ) तथा गेहूं और धान के अवशेषों से एथनॉल का कच्चा माल तैयार किया जा सकता है। हालांकि ऐसा एथनॉल राब से बनने वाले एल्कोहल की तुलना में थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले पर्यावरण नुकसान को रोककर यह भरपाई भी कर देता है। अच्छी बात यह है कि तेल विपणन कंपनियों ने इस विचार का समर्थन किया है और 11 राज्यों में ऐसी एथनॉल रिफाइनरी लगाने का काम चल रहा है। इस पर आगे और जोर देने की आवश्यकता है।

गैर खाद्य और तेजी से विकसित होने वाले शैवालों की मदद से एथनॉल बनाने की दिशा में शोध ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। ऐसी नवाचारी तकनीक की मदद से पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसा करने से पर्यावास अथवा खाद्य सुरक्षा पर कोई बुरा असर भी नहीं होगा।

अजय मोहंती

भाजपा का घटता आधार मगर हिंदुत्व का प्रसार

भले ही भाजपा देश के कुछ ही महत्त्वपूर्ण राज्यों में सत्तारूढ़ है लेकिन हिंदुत्व की उसकी विचारधारा पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

आप सब ने गिलास के आधा भरा या आधा खाली होने का किस्सा तो सुना ही होगा। इंडिया टुडे समूह के उस बहुचर्चित ग्राफिक को भी इस तरह देखा जा सकता है जिसमें 2017 से अब तक देश के राजनीतिक मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तुलनात्मक विस्तार को दर्शाया गया है। पहली नजर में ग्राफिक बताता है कि इन दो वर्षों में देश के राज्यों पर भाजपा का शासन 71 फीसदी से घटकर 40 फीसदी रह गया। ऐसा तब है जब आपको लग रहा होगा कि पार्टी की लोकप्रियता चरम पर है और मोदी के अधीन उसका वर्चस्व बेहद मजबूत है।

यह गिलास के आधा खाली होने वाला तर्क है। आधे भरे गिलास वाली दलील कहती है कि गत मई के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालिए। राजनीतिक हकीकत साफ नजर आती है। समूचे उत्तर भारत, अधिकांश तटीय इलाकों तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर दोबारा आम चुनाव हों तो भी नतीजे मई 2019 से अलग नहीं होंगे। तो मोदी के आलोचक किस बात का जश्न मना रहे हैं?

राजनीतिक हकीकत जटिल और बहुस्तरीय है और भगवा रंग की कई छवियां दिखाती है। आइए इन परतों को उघाड़ते हैं:

■ मोदी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन इंदिरा गांधी जैसा नहीं है। दूसरी तरह देखें तो देश का मतदाता इंदिरा युग से अधिक परिपक्व है। वह लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग-अलग चयन करता है।

ऐसे में इंदिरा की तरह मोदी भी चाहें तो अपनी पार्टी के टिकट पर एक खंभे तक को चुनाव जिता सकते हैं लेकिन केवल लोकसभा में। इंदिरा की तरह वह इस जादू को विधानसभा में नहीं दोहरा सकते। महाराष्ट्र का मामला थोड़ा जटिल है। हरियाणा के बारे में सोचिए। लोकसभा चुनाव के पांच महीने के भीतर हरियाणा में पार्टी का मत प्रतिशत करीब 22 फीसदी गिरा और 58 फीसदी से घटकर 36 फीसदी रह गया। तमाम दावों के बावजूद पार्टी को बहुमत तक नहीं मिल सका। जबकि हरियाणा में गहरी सैन्य और राष्ट्रवादी परंपरा है। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के वोट सीमित हैं और चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के 11 सप्ताह के भीतर हुए थे।

इससे पीछे जाएं तो 2014 में पूरा सफाया करने के बाद भी मोदी 2017 के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम में वैसी जीत नहीं पा सके। 2015 में दिल्ली और उसके बाद पंजाब में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में मामला एकदम करीबी रहा। कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ सत्ताविरोधी माहौल तथा बेल्लारी बंधुओं के साथ शर्मनाक समझौते के बावजूद भाजपा को बहुमत नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के अलावा जिन राज्यों में भाजपा हारी या निर्णायक जीत पाने में नाकाम रही, उन सभी में उसे लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। यहां तक कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसे शानदार जीत मिली।

■ सबसे अहम, इंदिरा युग में जहां एक दल के दबदबे को स्वीकार कर लिया गया था, उसके उलट देश अब अधिक संघीय व्यवस्था वाला हो गया है। यदि मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए अपने चयन में अंतर करता है तो भले ही मतदाता भाजपा के विरोधी न हों लेकिन इससे नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, वाई एस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं का साहस बढ़ता है जो भाजपा के बड़े शत्रु नहीं हैं।

यह केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे भाजपा के शत्रुओं को भी सुकून देता है। लोकसभा चुनाव में संघर्ष के छह महीने बाद तीन उपचुनावों में ममता बनर्जी को जीत मिली है। दो सीटों पर तो बहुत भारी अंतर से।

तीसरी श्रेणी के जो क्षेत्रीय नेता इससे प्रसन्न होंगे वे भाजपा के साझेदार हैं। इनमें नीतीश कुमार शीर्ष पर हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। इस श्रेणी में प्रफुल्ल कुमार महंत असम में और दुष्यंत चौटाला हरियाणा में आकांक्षा पाल सकते हैं।

■ सर्वेक्षण भाजपा के अधीन 17 राज्य बता रहा है जो आधा सच है। इनमें से कुछ मसलन बिहार और हरियाणा में उसकी साझेदारी ऐसे दलों से है जिनसे उसकी वैचारिकी बिल्कुल नहीं मिलती। मेघालय, नगालैंड और मणिपुर को अभी भी भाजपा की पहुंच वाले राज्य नहीं माना जा सकता। सिक्किम और मिजोरम राजग के हिस्से हैं लेकिन भाजपा के नहीं। एक अनकहा सच यह है कि भाजपा के पास केवल तीन बड़े राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। कर्नाटक की स्थिति से सभी वाकिफ हैं।

■ मोदी-शाह के उदय के बाद भाजपा ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। हिंदी प्रदेशों और दो बड़े पश्चिमी प्रदेशों में जीत के साथ देश पर राज। क्योंकि यहां वहां कुछ छोटी मोटी सफलताओं के साथ ऐसा आसानी से हो सकता था।

अगर इसे राज्यों में नहीं दोहराया जा सकता तो आपका मुकाबला संघवाद से है। यानी आपको मुख्यमंत्रियों से बातचीत करनी होगी, कुछ लेनदेन पर सहमति देनी होगी और इस हकीकत के साथ जीना होगा कि विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों में पुलिस और कानून व्यवस्था पर उनका राज होगा। हो सकता है कुछ राज्य आयुष्मान भारत जैसी आपकी अच्छी और बड़ी योजना तक को लागू करने से मना कर दे। उनको आदेशित नहीं किया जा सकता है। कई बार उनसे समानता का व्यवहार करना होता है। इसके लिए तौर तरीकों में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री अक्सर जिस सहकारी संघवाद की बात करते हैं वह केवल मंत्र नहीं बल्कि आवश्यकता है।

■ महाराष्ट्र पर नजर डालें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने शिवसेना का साथ इसलिए दिया क्योंकि दोनों दल अस्तित्व और सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। परंतु शिवसेना क्यों अलग हुई? इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रांत में भाजपा के विस्तार के साथ उसकी वैचारिक जमीन खतरे में है। शिवसेना की बगावत सीधे-सीधे एक दलके दबदबे से बचाव का उसका तरीका है।

■ केंद्र-राज्य संबंध सन 1989 से 2014 के बीच के 25 वर्ष वाले दौर में लौट सकते हैं। महाराष्ट्र से आ रही आवाजों को सुनिए: बुलेट ट्रेन का विरोध, मेट्रो के खिलाफ धमकियां। आंध्र प्रदेश ने अमरावती योजना रद्द कर और सिंगापुर से लेकर खाड़ी के लूलू समूह तक विदेशी साझेदारों को बाहर करके देश की एफडीआई के अनुकूल होने की छवि पर सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी गले लगाना होगा जैसे वह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को लगाते हैं।

■ इन सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी। ममता बनर्जी भले ही इसे खारिज करने वाली पहली नेता हों लेकिन संभावना यही है कि अधिकांश गैर भाजपा शासित राज्य इस विभाजनकारी, खतरनाक और अपने प्रतिकूल विचार को अस्वीकार करेंगे। पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को अपने जनमत से निपटना होगा जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ है। ऐसे में देखें तो एनआरसी का क्रियान्वयन करना मुश्किल ही है। यह चुनावी कारणों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाला विचार बना रहेगा। वैसे ही जैसे तीन दशक तक राम मंदिर रहा। एनआरसी-सीएबी के मेल के रूप में इसे आगे बढ़ाना मुश्किल है।

■ आखिर में अगर आपको लग रहा है कि मैं केवल भाजपा की कमियां गिन रहा हूं तो ग्राफ को एक बार पुन: देखिए। भगवा विस्तार सिमटता दिख रहा है। यह सीमित चुनावी हकीकत है। वैचारिक तस्वीर को देखिए तो पूरे भारत में आपको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जिसने अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना तो दूर, उसका स्वागत न किया हो।

बीते दशकों में भाजपा और आरएसएस के इन पसंदीदा मुद्दों ने भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण किया है। अब कश्मीर और राम मंदिर बल्कि समान नागरिक संहिता पर भी आम सहमति बनती दिख रही है। यहां तक कि केरल की वाम मोर्चा सरकार भी सबरीमला में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने का साहस न कर सकी। राहुल गांधी भी सार्वजनिक रूप से अपने जनेऊ का प्रदर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं और उच्च ब्राह्मण गोत्र दर्शाते हैं।

भारतीय मानचित्र के राजनीतिक रंग अब भाजपा और आरएसएस के भगवा रंग में रंग चुके हैं। भाजपा न सही, आरएसएस अब अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर अवश्य इस पर सहमत होते।

एलजीबीटीक्यू समुदाय को लेकर पूर्वग्रह से ग्रस्त है कारोबारी जगत

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

सर्वेक्षण में निष्कर्ष यह रहा कि भारतीय कारोबारी जगत में समलैंगिक समुदाय को लेकर पूर्वग्रह का भाव है। विभिन्न कंपनियों के जिन 1,137 पेशेवरों से बात की गई उनमें से 77 फीसदी ने कहा कि उनका ऐसा कोई सहयोगी नहीं है जो एलजीबीटीक्यू समुदाय से ताल्लुक रखता हो

भारत सरकार पहले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में शामिल होने की प्रक्रिया में थी लेकिन बाद में ऐन वक्त पर उसने अपने कदम वापस ले लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि देश का कारोबारी जगत यही मानता है कि वह अगले 25 वर्ष की अवधि में रखते हुए चीनी उद्यमों से मुकाबला नहीं कर सकता। आरसेप की वार्ताओं में 25 वर्ष की समायोजन अवधि की बात कही गई है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के कारोबारी जगत के दिग्गज सरकार के समक्ष खड़े होने के मामले में भीरू हैं। यदि कभी कोई मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सार्वजनिक रूप से छोटी सी भी आलोचना करता है तो यह हमेशा सुर्खियां बन जाती है। अब ऐसा लगता है कि देश का कारोबारी जगत नए लोगों को काम पर रखने के मामले में भी प्रतिगामी है।

यहां मेरा तात्पर्य कॉर्पोरेट जगत में लैंगिक विविधता की कमी से नहीं है। हालांकि यह भी सच है। हम बात कर रहे हैं बेनेट कोलमैन मीडिया समूह के स्वामित्व वाले जॉब पोर्टल टाइम्सजॉब के एक सर्वेक्षण की जो विविधता और समावेशन पर आधारित था। सर्वेक्षण का सबसे अहम निष्कर्ष यह रहा कि भारतीय कारोबारी जगत में समलैंगिक समुदाय को लेकर पूर्वग्रह का भाव है। विभिन्न कंपनियों के जिन 1,137 पेशेवरों से सर्वे में बात की गई उनमें से 77 फीसदी ने कहा कि उनका ऐसा कोई सहयोगी नहीं है जो एलजीबीटीक्यू (समलैंगिक, ट्रांसजेंडर तथा ऐसे अन्य) समुदाय से ताल्लुक रखता हो। जबकि 83 फीसदी ने कहा कि वरिष्ठ पदों पर ऐसा कोई नहीं जो वैकल्पिक यौन रुझान रखता हो।

यहां यह सवाल है कि आखिर सर्वेक्षण में शामिल कर्मचारियों ने अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों की यौन प्राथमिकताओं से जुड़े सवालों के जवाब कैसे तलाशे होंगे। यह विचार भी अकल्पनीय है कि देश के कारोबारी जगत में कोई समलैंगिक काम नहीं करता होगा लेकिन यह विषय अभी भी इतना वर्जित है कि कार्यस्थल पर वैकल्पिक यौनिक रुझान वाले लोग गुपचुप रहना ही अधिक बेहतर मानते हैं।

इस अवधारणा में चकित करने वाली कोई बात नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 हटाए जाने के बावजूद कॉर्पोरेट जगत में इस विषय को लेकर इतनी अधिक खामोशी है। यह अपने आप में बताती है कि समलैंगिकता को लेकर किस कदर भेदभाव वाला माहौल है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों का मुद्दा जनसंपर्क विभागों के लिए भी मायने नहीं रखता जबकि कारोबारी सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के तहत बनने वाले शौचालयों और गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की तमाम खबरें छाई रहती हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि करीब 65 फीसदी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें धारा 377 के समाप्त होने के बाद भी नीतियों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हालांकि सर्वेक्षण ने यह नहीं बताया कि जिन 35 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ बदलाव दर्ज किया है, उन्होंने किस प्रकार के बदलाव कंपनियों में देखे।

आखिर किस तरह के नीतिगत बदलाव की अपेक्षा की जानी चाहिए? सबसे बुनियादी है समलिंगी साथियों (अभी समलिंगी विवाह को वैधानिक मंजूरी नहीं है) और उनके बच्चों को तमाम सुविधाएं प्रदान करना। कुछ कंपनियों ने अपनी मानव संसाधन नीतियों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए गोदरेज समूह और इन्फोसिस ने बिना लिंग का उल्लेख किए 'साथी' को ये सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। ओयो समूह की बीमा नीति में भी 'अन्य' को शामिल किया गया है।

समस्या का एक बड़ा हिस्सा यह है कि देश के बैंकिंग और बीमा उद्योग की नीतियों में अभी ऐसे बदलाव बाकी हैं जिनकी मदद से खाताधारक ऐसे लोगों को लाथार्थी बना सकें जो उनके रिश्तेदार न हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस समस्या से निजात पाने के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं से बीमा कराती हैं। उनके पास ऐसी पेशकश रहती है। परंतु उनके यहां भारतीय कामगार तबके का बहुत छोटा हिस्सा काम करता है। ऐसी पहल देश के कारोबारी जगत के समलैंगिकता विरोधी माहौल में बहुत मामूली हैं। आश्चर्य नहीं कि 54 फीसदी लोगों ने कहा कि उनकी कंपनी कभी एलजीबीटीक्यू समुदाय के किसी सदस्य को काम पर नहीं रखेगी।

सर्वेक्षण में कॉर्पोरेट जगत में दिव्यांग पेशेवरों और महिलाओं को काम पर रखने की स्थिति को लेकर और निराश करने वाली सूचनाएं हैं। इनमें से तमाम बातें इतनी स्पष्ट हैं कि अब लोग इन पर टिप्पणियां भी नहीं करते। निजी क्षेत्र के प्रवर्तक निहायत सांप्रदायिक भी हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट अरसा पहले इस बात को रेखांकित कर चुकी है। परंतु देश के कारोबारी जगत के अधिकांश हिस्से में व्याप्त संस्कृति के बारे में एक निष्कर्ष दिलचस्प दृष्टि डालता है। करीब 40 फीसदी लोगों ने कहा कि कार्यस्थल पर किसी के बारे में राय बनाने में शारीरिक प्रस्तुतिकरण, जातीयता और व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकता की अहम भूमिका है। यह मानव स्वभाव है लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे प्रबंधन को क्षमता और प्रतिभा को भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि आखिर क्यों 21वीं सदी में देश के कारोबारी समूहों की कार्य संस्कृति पर 20वीं सदी की छाप है, उन्हें ऐसे निष्कर्षों से मदद मिल सकती है।

कानाफूसी

चुनाव की तैयारी

बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी प्रदेश में पिछले अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को हटाकर पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले राजनेता जगदानंद सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सिंह के बारे में सामने आई जानकारी के मुताबिक वह विवादों से दूर ही रहते हैं तथा उनका स्वभाव भी काफी शांत माना जाता है। स्थानीय स्तर पर चल रही खबरों पर भरोसा करें तो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद के वारिस और उनके बेटे तथा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूर्वे से कतई प्रसन्न नहीं थे। बिहार में अगले वर्ष यानी 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव करीब आने के साथ ही पूर्वे के स्थान पर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एक मकसद पार्टी पार्टी द्वारा राजपूतों तथा उच्च वर्ग के अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी हो सकता है। अभी यह तबका पार्टी के साथ नहीं रहा है। यह बात महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राजद को आमतौर पर यादवों और मुस्लिमों के दल के रूप में ही पहचाना जाता है।

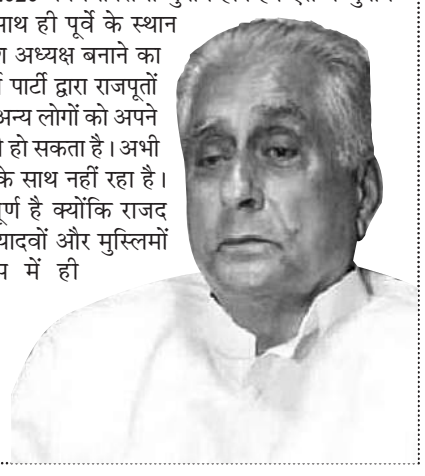

आपका पक्ष

सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं हजारों बेकसूर

देश में हर साल औसतन 19,620 बेकसूर लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इन लोगों का कसूर इतना है कि वे सड़क पार कर रहे होते हैं या फिर सड़क के किनारे चलते हैं। यह आंकड़ा सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले कुल लोगों की संख्या का 12 प्रतिशत है। सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर वाहन सवार की मौत होती है लेकिन पैदल चलने वाले बेकसूर लोग भी वाहनों की लापरवाही के कारण मारे जाते हैं। परिवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,785 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें 15,746 पैदल यात्री थे। वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,47,913 लोगों की जान गई जिनमें 20,457 पैदल यात्री थे। वर्ष 2018 में 1,51,417 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए जिनमें 22,656 पैदल यात्री थे। इन तीन वर्षों में औसतन 19,620 बेकसूर लोग वाहनों की चपेट में मारे गए हैं। सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक मामले तमिलनाडु में सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना हैं। तमिलनाडु में वर्ष 2016 में 2,966, वर्ष 2017 में 3,507 और वर्ष 2018 में 768 पैदल यात्रियों की जान गई थी। महाराष्ट्र में वर्ष 2016 में 2,103, वर्ष 2017 में 1,831 और वर्ष 2018 में 2,515 पैदल यात्रियों की मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में 1,627, वर्ष 2017 में 1,280 और वर्ष 2018 में 1,504 पैदल यात्री मारे गए थे। सरकार ने पैदल यात्रियों की सुविधाओं के दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। सरकार पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, फुट ओवरब्रिज तथा अन्य सुविधाओं पर गौर कर रही है। सड़क पार करते समय लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोग काफी जल्दबाजी में रहते हैं। लोग जहां जगह मिले वहां से सड़क पार करने लग जाते हैं। इस लापरवाही के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। सड़क के बीच में डिवाइडर या लोहे की ग्रिल लगाई जाती है जिससे लोग सड़क पार नहीं कर सके। लेकिन कुछ लोग लोहे की ग्रिल को फांद कर सड़क पार करने लगते हैं। जिससे कई बार तेज गति से आ रही गाड़ी के सामने अचानक से आ जाते हैं। इस स्थिति में दुर्घटना हो जाती है और दोष वाहन चालक पर मढ़ दिया जाता है। अत: सरकार को इसपर विचार करके उचित उपाय खोजने की जरूरत है।

अंकुर सिंह, नई दिल्ली

देश में हर साल औसतन 19,620 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है

विकास में महिलाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण

देश में महिलाओं की स्थिति आजादी के बाद से बहुत बदली नजर आती है। लेकिन इस स्थिति को सबकुछ नहीं माना जा सकता है। अगर हमें सुसभ्य, सुंदर समाज का निर्माण करना है तो हमें महिलाओं को भी उसी दिशा में कार्य कराना होगा। अर्थात लिंग विभिन्नता को छोड़कर समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकती है। उसी प्रकार हमारा समाज भी सिर्फ पुरुषों के बलबूते ही सबकुछ हासिल नहीं कर सकता है। हमें चाहिए कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। बहुत सी महिलाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी कितनी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर उन्हें दुर्भाग्यवश मारा नहीं जाता है तो उन्हें असमानता की दृष्टि से देखा जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई पहल शामिल की जाती हैं जो कुछ हद तक प्रभावित भी करती हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी पहल शुरू की गई है। इसमें एक से छह वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को सप्ताह में तीन दिन अंडे दिए जाएंगे। जो अंडा सेवन नहीं करते हैं उन्हें फल दिए जाएंगे। यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

सुप्रिया कुमारी, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

उपक्रमों का विनिवेश सही, लेकिन हाथ में रहे लगाम

अजय मोहंती

देश के विकास में अहम भूमिका

बड़ी विनिवेश योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों की भूमिका को कम करके , विनिवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके सुचारु रूप से चलाने से देश के विकास को गति मिलेगी। सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा जिससे जिससे भारत सरकार आर्थिक मंदी समस्या से निपट सकेगी।

स्वीकृति गुप्ता
खागा

कर्मियों-अर्थव्यवस्था के हित में नहीं

हकीकत यह है कि विनिवेश के तहत सरकारी कंपनियों में कुछ फीसदी बेचने से खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन कंपनियों का स्वामित्व पूरी तरह निजी क्षेत्र को दे दिया गया तो कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कर्मचारियों का अहित होगा और नौकरी पर खतरा हो जाएगा। देश में बेरोजगारी है, देसी कंपनियां संकट में हैं और बैंकों की भी हालत ढीली है। सरकार कर संग्रह के मोर्चे पर विफल रही है, जिस कारण बार-बार कर जमा करने और सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया जाता है। सरकारी कंपनियों की जमीन पर नजर गड़ाए निजी उद्योगपतियों के हाथों मुनाफे वाले उपक्रमों की बिक्री से वाहवाही तो मिलेगी, लेकिन आर्थिक संकट बढ़ जाएगा। भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना उचित होगा। सरकार जिम्मेदारियों से भागने के बजाय इन्हीं कपंनियों से बेहतर प्रदर्शन कराए।

विशाल कुमार शर्मा
मोतिहारी, बिहार

पेट्रोलियम कंपनियों को विनिवेश न हो

सरकार विनिवेश इसीलिए करती है ताकि घाटे वाली सरकारी कंपनियों का वित्तीय बोझ उसे नहीं उठाना पड़े। 1996 में विनिवेश आयोग ने 57 कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की थी। मौजूदा सरकार ने उन्हीं सिफारिशों को अमल में लाकर कई कंपनियों का विनिवेश करने का फैसला किया है। सरकार को इससे राजकोषीय घाटा कम करने में मदद तो मिलेगी, लेकिन बीपीसीएल जैसी मुनाफे वाली कंपनी में अपनी 35 फीसदी हिस्सेदारी निजी कंपनी को बेचना ठीक नहीं है क्योंकि निजी कंपनी का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। आगे चलकर निजी कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूल सकती हैं, इसलिए पेट्रोल, डीजल, गैस पर ऐसी कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार को पेट्रोल, डीजल व गैस जैसी निजी कंपनियों का मूल्य का नियंत्रण एवं नियमन अपने हाथ में रखना चाहिए। तभी विनिवेश नीति उचित एवं राष्ट्रहित में साबित होगी।

नितेश दिनेशचंद्र त्रिपाठी
नागपुर, महाराष्ट्र

वास्तविक क्रियान्वयन की जरूरत

सरकार विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 50 फीसदी से कम करना चाहती है, लेकिन उनकी लगाम पूरी तरह अपने हाथों में रखना चाहती है। विनिवेश से नए निवेशकों का रुझान बढ़ेगा और जो रकम मिलेगी, उसे सरकार दूसरे क्षेत्रों में लगा सकती है। विनिवेश उचित निर्णय है, जिससे सरकार 1 लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कार्य संस्कृति में सुधार, शुद्ध लाभ में वृद्धि, काबिल मानव संसाधन की उपलब्धता हो सकती है और प्रतिभा पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था बनाए बगैर भारत का विकास लगातार नहीं हो सकता। सरकारी कंपनियों का विनिवेश उचित है मगर क्रियान्वयन वास्तविक तरीके से होना चाहिए।

डॉ रसिकेश
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

अतिरिक्त धन के लिए ही विकल्प

विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ ही हो चुकी थी। जब तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाने अर्थात विनिवेश की शुरुआत की थी। इसकी मुख्य वजह उपक्रमों का लंबे समय से घाटे में चलना था। क्योंकि सरकार इन पर किया जाने वाला खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थी। वास्तव में इस घाटे की वजह से बजट घाटा बढ़ रहा था। जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। अत: 5 कंपनियों में अपनी 51 फीसदी की भागीदारी को कम करने का निश्चय किया। ताकि लंबित विकास योजनाओं के लिए धन उपलब्ध हो सके और आर्थिक सुस्ती को थामकर सरकार राजकोषीय घाटे को भी नियंत्रित कर सके। इस प्रकार विनिवेश के माध्यम से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर्जमुक्त पूंजी प्राप्त हो सकेगी।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

विनिवेश से सुधरेगी अर्थव्यवस्था

भारत सरकार अपने करीब 7 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे को साधने के लिए अपनी कंपनियों का निजीकरण और विनिवेश करने जा रही है। विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की सूची दी गई, जिनमें से 24 के विनिवेश को मंजूरी मिल गई है। सरकार का इस साल विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। सरकार इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहती है। विनिवेश तब हो रहा है, जब बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। घरेलू कंपनियों के पास पूंजी नहीं है। इनमें से अधिकतर कर्जदार है और बैंकों की हालत भी ढीली है। कई सरकारी कंपनियों में गैर पेशेवर तरीके से कामकाज के कारण घाटा हो रहा है, इसलिए उनका निजीकरण होना चाहिए ताकि कामकाज का तरीका बदले। कंपनी को निजी हाथों में बेचने से मिली रकम का इस्तेमाल जनता के लिए किया जाए।

कुमारी कबिता
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

लाभदायी होगा संतुलित विनिवेश

सरकार धनाभाव के कारण विनिवेश जैसा कदम उठाती है। सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री संतुलित होनी चाहिए। भारत में केंद्र सरकार अनेक लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि वितरित करती है। बढ़ते समय के साथ ऐसी वितरित धनराशि की तुलना में सरकारी पीएसयू का लाभांश बढ़ने के बजाय घटता ही गया। सरकारी कंपनियों की बिक्री का निर्णय इसलिए लिया जा रहा है। विनिवेश के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के खरीदार अपना लाभ देखकर इन्हें खरीदेंगे। उनकी ओर से कुछ कठोर शर्तें भी सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। अपने आय-व्यय के संतुलन के लिए ही सरकारें ऐसे कदम उठाती हैं। विनिवेश का निर्णय राजस्व घाटा और आर्थिक सुस्ती को देख लिया जा रहा है। यदि सुशासन हो, शासन-प्रशासन के कार्य में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और लोक कल्याण का अंतिम हित परिलक्षित होता है तो सरकारी कंपनियों का विनिवेश राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में लाभकारी ही रहने की आशा है।

विकेश कुमार बडोला
कोटद्वार, उत्तराखंड

उचित है सरकारी कंपनियों में विनिवेश

विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या उपक्रमों की कुछ हिस्सेदारी को शेयर या बॉन्ड के रूप में बेचती है। इससे मिलने वाले धन का उपयोग सरकार या तो उस कंपनी को बेहतर बनाने में करती है या दूसरी योजनाओं में लगाती है। विनिवेश का मकसद कंपनी का प्रबंधन बेहतर बनाना भी है। इस समय आर्थिक सुस्ती और सुस्त कर वसूली से सरकारी खजाने पर दबाव है। ऐसे में सरकार अपने दम पर सरकारी कंपनियों पर किए जाने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकती। विनिवेश के जरिये सरकार घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे को कम करके उनको फायदे में लाना चाहती है। विनिवेश मकसद बजट घाटे को भी कम करना और इससे मिलने वाले धन का उपयोग देश के विकास में करना भी है। इस तरह देखा जाए तो सरकारी कंपनी और सरकार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विनिवेश उचित है।

जोगेंदर सरना
लुधियाना, पंजाब

इन कंपनियों की हालत सुधारे सरकार

केंद्र सरकार आर्थिक सुस्ती के कारण अपने कर वसूली लक्ष्य से पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने और बढ़ते राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश पर जोर दे रही है। लेकिन इस समय देश में बेरोजगारी का माहौल है। ऐसे में विनिवेश की वजह से नौकरियों की स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए ही देश में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े मजदूर संगठन भी विनिवेश का विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का आशंका है कि सरकार विनिवेश के बाद इन कंपनियों के पूर्ण निजीकरण की दिशा में कदम उठा सकती है। कुछ लोगों को आरोप है कि पहले सरकार ने अपनी नीतियों के कारण इन सरकारी कंपनियों को मुश्किल हालत में डाल दिया और अब उनको बेचने का माहौल बना रही है। लिहाजा सरकार को विनिवेश की बजाय इन कंपनियों की हालत सुधारने पर व्यावहारिक रुख अपनाकर जरूरी कदम उठाने चाहिए।

मानविक शर्मा
दिल्ली

घाटे वाली कंपनियों का विनिवेश उचित

मोदी सरकार ने इस साल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू)के विनिवेश से करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग ने विनिवेश के लिए करीब 40 पीएसयू की सूची तैयार की है, जिनमें काफी कंपनियां बीमारू यानी घाटे में हैं। लेकिन कुछ कंपनियां लाभ कमाने वाली भी हैं। ऐसे में जहां तक विनिवेश का सवाल है तो घाटे वाली और आगे भी इनकी कार्यशैली के आधार पर इनके लाभ में न आने की संभावना वाली कंपनियों का विनिवेश करना उचित है। आखिर इन कंपनियों की अक्षमता का बोझ सरकारी खजाने पर क्यों पड़े ? लेकिन सरकार को लाभ वाली पीएसयू का विनिवेश कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां बड़ी मेहनत से कारोबार कर और लाभ कमाकर अपने कर्मचारी और देश के विकास में महती भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा अपना खजाना भरने के लिए इन लाभकारी कंपनियों के विनिवेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अरविंद किरार
भोपाल, मध्य प्रदेश

रणनीति के साथ किया जाए विनिवेश

केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया पर काम कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने से पहले उचित रणनीति पर काम करना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि विनिवेश का लक्ष्य सरकारी हिस्सेदारी में कमी करना नहीं बल्कि राजकोष में अधिक से अधिक धन जमा करना है। इसलिए किसी भी कंपनी में विनिवेश प्रक्रिया अपनाने के बजाए लाभ वाली कंपनियों का विनिवेश किया जाए, जिससे अधिक से अधिक राशि सरकारी खजाने में जमा हो सके। सरकार को कम लाभ या घाटे वाली कंपनियों में प्रशसन के स्तर पर बदलाव करने चाहिए और उन्हें एक निर्धारित स्तर पर लाने के बाद ही विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

संदीप माहेश्वरी
नई दिल्ली

पेशेवर तरीके अपनाने की जरूरत

भारत का राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपये का है। इसका अर्थ यह है कि खर्च और कमाई में 6.45 लाख करोड़ रुपये के अंतर को पाटने के लिए सरकार ऐसी कंपनियों का निजीकरण और विनिवेश कर राशि जुटाना चाहती है। सरकार ने पांच कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाना है। जानकारों का मानना है कि पिछले 30 वर्षों में जिस तरह से सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया गया है वह विनिवेश नहीं था बल्कि एक सरकारी कंपनी के शेयर को दूसरी सरकारी कंपनी को बेचा गया। इससे सरकार का बजट घाटा तो कम हुआ है लेकिन इससे न तो कंपनी के शेयर पर फर्क पड़ता है और न ही कंपनी के कामकाज के तरीके बदलकर बेहतर होते हैं। यह विनिवेश ऐसे समय में हो रहा है जब देश में बेरोजगारी चरम पर है। वर्तमान में सरकार के पास पूंजी की सख्त कमी है। विनिवेश के पक्ष में तर्क यह है कि सरकारी कंपनियों में कामकाज का तरीका पेशेवर नहीं रह गया है और इस वजह से बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

उचित रणनीति के साथ लगाया जाए विनिवेश पर दांव

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक विनिवेश से 17,364 करोड़ रुपये की कमाई की है, लेकिन इनमें से 82 प्रतिशत हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) से अर्जित किया है, न कि सहायक कारोबारी इकाइयों में हिस्सेदारी की बिक्री से। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से संबंधित विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब मात्र चार माह का समय शेष बचा है। इसलिए अब सरकार को पीएसयू उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री के लिए कुछ अहम कदम उठाने चाहिए। जनवरी 2018 के बाद से से कम बाजार पूंजीकरण वाले कुछ पीएसयू के शेयरों में 25-64 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है। खनिज संपदा वाले दो पीएसयू के शेयरों में जनवरी 2018 के बाद से 46 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत की कमी आई। दूसरी ओर बहुत कम पीएसयू ऐसे भी हैं जिनके शेयर अधिक कीमत पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कुछ छोटे पीएसयू का आय-कीमत अनुपात (पीई) एकल अंकों में है लेकिन यह भी सच है कि कुछ 60 पीई से भी अधिक पर कारोबार कर रहे हैं। इसलिए, सरकार को उचित एजेंसी की मदद से बाजार में सार्वजनिक उपक्रमों के मूल्यांकन की निगरानी करनी चाहिए और जब ऐसी कंपनियों का मूल्यांकन निर्धारित स्तर पर पहुंच जाए तो इनकी बिक्री पर दांव लगाया चाहिए। सरकार को फिलहाल कारोबार में गिरावट वाले छोटे सरकारी उपक्रमों में रणनीतिक बिक्री पर रोक लगानी चाहिए और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए संबंधित कारोबार में विनिवेश का निर्णय उचित समय आने पर ही करें। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ छोटे सरकारी उपक्रम लगातार मुनाफा कमाने के बावजूद, सरकार और शेयरधारकों दोनों के आर्थिक हितों को लेकर चिंतित नहीं हैं। इनमें से कुछ अपने आईपीओ आने के 2 से 9 वर्ष बाद भी आईपीओ की कीमत से कम कीमतों पर व्यापार करते हैं। सरकारी उपक्रमों में विनिवेश के मामले में सरकार को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखनी चाहिए और शेष हिस्सेदारी निजी उद्यमियों को सौंप देनी चाहिए।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

जी. चोकालिंगम
संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, इक्विनोमिक्स रिसर्च

अर्थव्यवस्था व पीएसयू के लिए फायदेमंद है विनिवेश

इस समय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का माहौल और सरकार राजस्व वसूली के लक्ष्य को हासिल करने में भी मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसे में सरकार राजकोषीय स्थिति में संतुलन को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में विनिवेश पर जोर दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनिवेश से अर्थव्यवस्था, उद्योग, सरकार और आमजन को क्या फायदा होने वाला है ? विनिवेश अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। पीएसयू में विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र का दखल होने से नई तकनीक, नए विचार व नई दिशा का आगमन होता है। जिससे पीएसयू को तेजी से विकास करने में मदद मिलती है। पीएसयू के वृद्धि करने का सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को होता है। पीएसयू के विनिवेश से निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं और पीएसयू में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। आमतौर पर माना जाता है कि निजी क्षेत्र के प्रबंधन के काम करने का तरीका ज्यादा पेशेवर और बेहतर होता है। जिससे संबंधित कंपनी के विकास करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे में पीएसयू में निजी क्षेत्र के पेशेवरों के आने से पीएसयू ज्यादा तेजी से बढ़ सकेंगी। इससे रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। विनिवेश से रोजगार घटने की धारणा गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र घाटा सहने के लिए तो पीएसयू में निवेश नहीं करेगा ? इसी तरह मुनाफे वाली कंपनियों में विनिवेश पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। इन कंपनियों में विनिवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र के पेशेवरों के आने से इनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। इससे भी रोजगार के मौके और बढ़ेंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए घाटे वाली पीएसयू के साथ ही मुनाफे वाली पीएसयू में विनिवेश जरूरी और उचित है। अब तक पीएसयू में विनिवेश के अनुभव बताते हैं कि विनिवेश अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग व सरकार हित में रहा है। कुल मिलाकर पीएसयू में विनिवेश से जहां सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं पीएसयू की आर्थिक स्थिति भी सुधरने की संभावना है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

डॉ. एस पी शर्मा
मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री

पुरस्कृत पत्र

विनिवेश नहीं समाधान निजीकरण जरूरी

घाटे में चलने वाली सार्वजनिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना कठिन है। ऐसे में इन्हें चलाने के लिए सरकार के पास पहला रास्ता इन इकाइयों में विनिवेश और दूसरा इनका निजीकरण है। विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक इकाइयों की समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि इनका कामकाज सरकारी ढंग से ही चलता रहता है। केवल सतही सुधार होते हैं और मूल चरित्र पूर्ववत बना रहता है। ऐसे में वित्त मंत्री को चाहिए कि वह इन सार्वजनिक इकाइयों की मूल समस्या पर ध्यान दें। जिन क्षेत्रों में उद्यमियों ने क्षमता हासिल कर ली है, उनसे सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। तेल रिफाइनरी, बैंक, बीमा, कोयला, तांबे तथा अन्य खनिजों का खनन आदि निजी क्षेत्र आज सक्षम है। क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का पूर्ण निजीकरण होना चाहिए और इससे मिलने वाली रकम का उपयोग नए क्षेत्रों में नई इकाइयों को स्थापित करने में हो।

रवि प्रकाश
पटना, बिहार

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

फायदेमंद है विनिवेश

सरकारी कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश से फायदे के कयास ज्यादा हैं। अगर विनिवेश से लाभ देखें तो इससे राजकोषीय घाटे को भी कम किया जा सकता है, व्यावसायिक नियमों में उदारी लाकर हम यह दिखा सकते हैं कि सरकार नियामक की भूमिका निभा रही है। इसे भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक हितों को तबज्जो देने का प्रयास भी समझा जा सकता है। विनिवेश से प्राप्त रकम को ढांचागत विकास में लगाकर नए आयाम स्थापित करने के मौके भी हैं। मगर नुकसान यह है कि सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी। हालांकि सरकार पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती क्योंकि वह केवल दो कंपनियों का विनिवेश कर रही है। एक में आंशिक विनिवेश है और दो अन्य सरकारी कंपनियों का विनिवेश सरकारी कंपनियों को ही किया जा सकता है।

प्रदीप कुमार गुप्ता
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

स्थिति में सुधार संभव

सरकारी कंपनियों में विनिवेश कितना आवश्यक है ? इसके लिए यदि हम देश की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो स्थिति सहज स्पष्ट हो जाती है। सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में से सुरक्षा पर समुचित विकास किया गया है और आगे भी अपेक्षित है। परन्तु संरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इधर अधिकतर सरकारी कंपयिां सरकार पर आर्थिक एवं व्यावहारिक तौर से बोझ हैं। इन कंपनियों का पूरा अथवा कुछ हिस्सा विनिवेश करने से देश को दोहरा लाभ होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध होगा और साथ ही सरकार इन कंपनियों को अधिक लाभप्रद बनाकर से भी अपना राजस्व घाटा पूरा कर सकती है।

नंदिता दास
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

उचित नहीं है विनिवेश

केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपये का बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन आर्थिक सुस्ती का इस लक्ष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सरकार की जीएसटी वसूली लक्ष्य से कम हो रही है, जिससे राजस्व घाटे के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में कर वसूली लक्ष्य में पिछड़ने के कारण सरकारी खजाने को भरने के लिए केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर जोर दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार की नाकामी का खमियाजा सरकारी कंपनियों को उठाना पड़ेगा। सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दूसरे कदम उठाने चाहिए न कि विनिवेश के माध्यम से सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने पर जोर देना चाहिए।

दिव्या सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

सुधारात्मक कदम उठाये सरकार

विनिवेश बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि सरकारी कंपनियों का काम करने का ढंग विनिवेश भर से नहीं बदलेगा। अगर मोदी सरकार को लगता है कि घाटे वाली बीमारू कंपनी निजीकरण की महरमपट्टी से ठीक हो जाएंगी तो गलत है। 1991 में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण नीतियों से भारत की आर्थिक तस्वीर बदल दी थी मगर नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। विनिवेश से रही-सही कसर भी निकल जाएगी। विनिवेश के जरिये ढेरों लोगों की रोजी-रोटी अधर में लटकाने के बजाय सरकारी कंपनियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। प्रयोगों से दूरी बरतनी चाहिए। अभी तो अर्थव्यवस्था की मरम्मत की जरूरत है।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -
कॉल दरों में इजाफा कितना जरूरी ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

पूर्वग्रह से परे होना चाहिए मध्यस्थ

अदालत से

एम जे एंटनी

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक बार फिर मध्यस्थ की स्वतंत्रता और तटस्थता की अहमियत पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का किसी विवाद या उसके परिणाम या फैसले में कोई हित है तो वह मध्यस्थ बनने के योग्य नहीं है और न ही वह किसी अन्य को मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की विवाद के समाधान की किसी भी योजना में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने कई फैसलों का हवाला देते हुए यह बात कही जिनमें निष्पक्षता के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि ऐसे विवादों से बचने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह कानून में 2015 में संशोधन किया गया था लेकिन यह मुद्दा बार-बार उठ रहा है। इस बार मामला परकिंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी इंडिया लिमिटेड वाद से जुड़ा है। न्यूयॉर्क की वास्तुकार कंपनी और मुंबई की एक कंपनी के कंसोर्टियम को गुंटूर में प्रस्तावित एम्स के लिए डिजाइनर सलाहकार नियुक्त किया गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के छह दिन बाद ही विवाद पैदा हो गया और कंसोर्टियम को अनुबंध खत्म करने का नोटिस दिया गया। जब कंसोर्टियम ने मध्यस्थता प्रावधान का सहारा लिया तो एचएससीसी के मुख्य प्रबंधक को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। कंसोर्टियम ने इसका विरोध किया करते हुए कहा कि एचएससीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इसके योग्य नहीं है और वह निष्पक्ष नहीं होंगे। न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराया और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया।

परिसीमा नियम का सवाल मध्यस्थ के हवाले

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक अन्य फैसले में कहा कि मध्यस्थता कानून का मकसद मध्यस्थता प्रक्रिया को स्वायत्तता देना और कम से कम न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। इसलिए अगर मध्यस्थ की नियुक्त हो गई या पंचाट गठित हो गया तो सभी सवालों और आपत्तियों का फैसला मध्यस्थता पंचाट करेगा। न्यायालय ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड वाद में अपने फैसले में यह बात कही। इस मामले में कोयला कंपनी ने मध्यस्थता का विरोध करने के लिए परिसीमा नियम का सहारा लिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसे मान लिया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिसीमा के मुद्दे का फैसला मध्यस्थ करेगा। उसने कहा कि न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विचार करने की जरूरत है। प्रारंभिक या परिसीमा के बाकी सभी मुद्दों पर फैसला मध्यस्थ को करना है। न्यायालय ने इस विवाद में एक पूर्व न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया।

जल प्रदूषण के लिए निकाय अधिकारियों पर मुकदमा

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) कानून के तहत नगरपालिका परिषद के निगम आयुक्तों और मुख्य अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले में कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी हीरा नायक वाद में स्थानीय निकाय अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई थी कि उन्होंने एक ऐसे जलमल शोधन संयंत्र से गंदा पानी छोड़ने की अनुमति दी थी जिसका लाइसेंस 2006 में ही खत्म हो गया था। इस संयंत्र के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके बजाय आरोपी लगातार गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ते रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी कंपनियां और स्थानीय शहरी निकाय को कानून के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि नगरपालिका परिषद एक कंपनी है।

दावे से अधिक मुआवजा

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क दुर्घटनाओं में पंचाट के पास पीड़ित को दावे से अधिक मुआवजा देने का अधिकार है। जब्बार बनाम महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम वाद में एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि न्यायालय दावे से ज्यादा मुआवजा नहीं दे सकता है। मोटर वाहन कानून की धारा 168 के तहत पंचाट या न्यायालय का काम उचित मुआवजा देना है। इस मामले में एक बस दुर्घटना के कारण फल विक्रेता को अपनी बाजू गंवानी पड़ी। वह 9 लाख रुपये का मुआवजा चाहते थे लेकिन वह न्यायालय की फीस चुकाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने 3 लाख रुपये का मुआवजा मांगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलता है तो वह दावे से अधिक रकम को न्यायालय की फीस के तौर पर चुकाने को तैयार हैं। पंचाट ने केवल 1.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया। अपील पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना के दिन से 9 फीसदी ब्याज के साथ मुआवजे की राशि 5 लाख रुपये कर दी।

आयकर मामले में वैकल्पिक उपाय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब आय कर कानून में वैकल्पिक उपाय दिया गया है तो उच्च न्यायालय में जाने से पहले उसका इस्तेमाल होना चाहिए। न्यायालय ने जेनपैक्ट इंडिया बनाम उपायुक्त वाद में अपील खारिज कर दी और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया। इस मामले में कंपनी के शेयर उसके एकमात्र शेयरधारक और होल्डिंग कंपनी जेनपैक्ट इंडिया इनवेस्टमेंट, मॉरीशस के पास मौजूद शेयरों को दो चरणों में वापस लाया गया।

इस बीच शेयरों की पुनर्खरीद से संबंधित कानून की धारा 115 क्यूए में संशोधन हो गया और इसके मुताबिक आकलन का आदेश दिया गया। कंपनी ने इसे चुनौती दी। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तर्क दिया कि संबंधित प्रावधान 2013 में लाया गया था। दरअसल भारत में सहयोगी कंपनियां कर बचाने के लिए शेयरों के पुनर्खरीद की आड़ में मॉरीशस की होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों को आय का वितरण कर रही थीं। इसी वजह से यह प्रावधान लाया गया था। विभाग ने 20 फीसदी की दर से कर मांगा। कंपनी ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की लेकिन राजस्व विभाग ने कहा कि कानून में इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपील भी खारिज कर दी।

निजी संपत्ति के ऊपर पारेषण लाइन

निजी संपत्ति के ऊपर बिजली पारेषण लाइन बनाने से अक्सर कई पक्षों के बीच मुकदमेबाजी होती है। संपत्ति मालिक इसके लिए राजी नहीं होते हैं, लाभार्थी इसकी मांग करते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी निर्बाध पहुंच चाहते हैं और सरकार को जनहित और आर्थिक विकास का संरक्षण करना होता है। सेंचुरी रेयॉन लिमिटेड बनाम आईवीपी लिमिटेड वाद में रसायन कंपनी आईवीसी की जमीन से पारेषण लाइन गुजारना चाहती थी।

आईवीसी ने इसके खिलाफ एक दीवानी अदालत में याचिका दायर की जिसने निर्माण पर रोक लगा दी। बंबई उच्च न्यायालय ने रोक के खिलाफ सेंचुरी रेयॉन की याचिका खारिज कर दी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कई शर्तों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दे दी। सेंचुरी भू मालिक को 20 लाख रुपये देगी और बिजली विभाग उस काम को पूरा कर सकता है जिस पर पहले ही बहुत काम हो चुका है। टेलीग्राफ कानून और बिजली कानून से संबंधित दीवानी मामला चलता रहेगा।

सीएमडी: दो कुर्सियां कितनी जरूरी

चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की भूमिकाओं को अलग करने संबंधी सेबी के आदेश पर प्रवर्तक परिवारों ने आपत्ति जताई है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि उनका विरोध समझ से परे है

सुदीप्त दे

हाल में मुंबई में कंपनी प्रशासन पर आयोजित सम्मेलन के दौरान आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस दिशानिर्देश पर राय मांगी गई थी जिसके तहत शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक (एमडी) के पद को अप्रैल 2020 से अलग-अलग करने की बात कही गई है।

बिड़ला ने अपने औद्योगिक समूह का उल्लेख करते हुए कहा, 'हमारे यहां एमडी और चेयरमैन को काफी लंबे समय से दो अलग-अलग भूमिकाओं में अलग किया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इन दोनों पदों को कैसे एक किया जा सकता है।' उन्होंने यह भी कहा कि यह काफी विडंबनापूर्ण होगा कि इन दोनों पदों की गतिविधियों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा, 'चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी को संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उस तरह की स्थिति में होने से डर लगता है। काम करने के लिहाज से वह काफी जटिल स्थिति होगी।'

हालांकि भारतीय उद्योग जगत के अधिकतर कारोबारी समूह के प्रवर्तक परिवार बिड़ला की इस राय से इत्तफाक नहीं रखते। सेबी के इस दिशानिर्देश को लागू करने के लिए अंतिम समय-सीमा अप्रैल 2020 है और इसलिए प्रबंधन ढांचे में बदलाव करने के लिए कंपनियों के पास कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में उद्योग जगत की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि प्रवर्तक परिवारों को सबसे अधिक परेशानी उस प्रावधान से है जिसके तहत कहा गया है कि गैर-कार्यकारी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संबंधित नहीं होना चाहिए।

विशेषज्ञों ने कहा कि प्रवर्तक परिवारों के लिए शीर्ष प्रबंधन के पदों को युक्तिसंगत बनाने और प्रबंधन निदेशक अथवा सीईओ पदों पर पेशेवरों को नियुक्त करने से अधिकतर प्रवर्तक परिवारों को तत्काल राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर उन्हें संबंधित प्रावधानों के तहत दोनों पदों को अलग करना पड़ेगा।

ऐसा नहीं है कि भारतीय उद्योग जगत में इस प्रकार के बदलाव नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके तहत चेयरमैन और एमडी/सीईओ के पदों को अलग किया गया है। और इसके कारणों को उजागर करना कठिन नहीं है।

कंपनी प्रशासन की विशेषज्ञ फर्म एक्सिलेंट इनेबलर्स के चेयरपर्सन और सेबी के पूर्व चेयमैन एम दामोदरन ने कहा, 'चेयरमैन तो बोर्ड का चेयरमैन होता है। बोर्ड की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि प्रबंधन अपना काम भलीभांति कर रहा है। एमडी प्रबंधन का प्रमुख होता है और वह बोर्ड में प्रबंधन की ओर से जवाब देने के लिए जिम्मेदार होता है।' उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चेयरमैन हितधारक समुदाय के लिए जवाबदेह है जो प्रबंधन से सही सवाल पूछने की उम्मीद करता है तो एक ही व्यक्ति इन दोनों जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकेगा?

दामोदरन का मानना है कि बोर्ड की भूमिका प्रबंधन को सकारात्मक चुनौती देने की होती है। उन्होंने कहा, 'यदि बोर्ड की यह भूमिका होगी तो जाहिर तौर पर इन दोनों भूमिकाओं को अलग कर देनी चाहिए।'

हालांकि टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन का मानना है कि यह अवधारणा अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए अधिक अनुकूल है। श्रीनिवासन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की भूमिकाओं को अलग करने के मुद्दे पर आपत्ति जताई है।

श्रीनिवासन ने कहा, 'कानून देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होने चाहिए। भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह अवधारणा प्रासंगिक नहीं है।' उनका मानना है कि भारत में अधिकतर प्रवर्तकों का अपने कारोबार में उल्लेखनीय हिस्सेदारी होती है और वे सबसे बड़े एकल शेयरधारक होते हैं। उन्होंने कहा, 'वे संपत्ति सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को आंख मूंदकर पश्चिम के नियमों को यहां लागू नहीं करना चाहिए।'

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर कविल रामचंद्रन का मानना है कि भारतीय उद्योग जगत के विरोध की जड़ें काफी गहरी हैं। उन्होंने कई वर्षों तक भारतीय कारोबारी परिवारों के प्रबंधन का अनुसंधान किया है और कई परिवारों को सलाह दी है। उन्होंने कहा, 'वास्तव में वे नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके लिए निर्णय ले अथवा कहे कि क्या करना चाहिए जबकि उनका मानना है कि वे चीजों को भलीभांति जानते हैं।'

हालांकि दामोदरन ने बीच का रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा, 'पहले से ही यह मान लेना कि संबंधियों की भूमिका सही नहीं है। हमने पुत्रों, भाइयों, बेटियों और बहनों को अपने बड़ों से अलग पदों पर काम करते हुए देखा है।' वह इस कानून को लागू करने के पक्ष में हैं। उन्होंने सुझाव दिया, 'जहां तक दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सवाल है तो उसे दो-तीन वर्षों में निपटाया जा सकता है। इसे लेकर उथल-पुथल मचाने की जरूरत नहीं है।'

रामचंद्रन का मानना है कि भारतीय उद्योग जगत के लिए यह बोर्ड की प्रशासन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक अवसर है। उन्होंने प्रवर्तक परिवारों को सलाह देते हुए कहा, 'उन्हें परिवार के बाहर से उच्च गुणवत्ता वाले सीईओ को तलाशना चाहिए और उसी आधार पर आगे इस भूमिका को दमदार बनाने की जरूरत है। उन्हें स्वतंत्र और अपने मूल्यों को साझा करने में समर्थ व्यक्ति तलाशना चाहिए।'

दिग्गजों की राय

चेयरमैन व सीईओ संबंधित नहीं होने चाहिए। मैं उस तरह की स्थिति में फंसने से डरता हूं।

कुमार मंगलम बिड़ला
चेयरमैन, आदित्य बिड़ला समूह

चेयरमैन कंपनी के निदेशक मंडल का चेयरमैन होता है जबकि एमडी उसके प्रति जवाबदेह है।

एम दामोदरन
पूर्व सेबी प्रमुख

नियमन देश की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होने चाहिए। भारत के लिए यह अवधारणा सही नहीं है।

वेणु श्रीनिवासन
चेयरमैन एवं एमडी, टीवीएस मोटर कंपनी

कार्वी मामले के सबक

नियमों के बेहतर क्रियान्वयन में है समाधान

श्रीमी चौधरी

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (केबीएसएल) मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निवारक आदेश से ब्रोकरों द्वारा फायदा उठाए जाने वाली खामियां उजागर हुई हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा नियमों को केवल सख्त बनाए जाने से उसका कारगर समाधान नहीं होगा। उनका मानना है कि कारगर समाधान के लिए मौजूदा नियमों का उचित क्रियान्वयन और बाजार के बिचौलियों जैसे स्टॉक एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज पर नजर रखने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले क्लीयरिंग सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल होने की जरूरत है। कार्वी प्रकरण ब्रोकरों द्वारा निवेशकों के धन को हड़पने की अपने प्रकार की पहली घटना नहीं है। यह करीब डेढ़ दशक पुराना मामला है जो स्टॉकब्रोकरों की निगरानी के अभाव के कारण लगातार उभर रहा है। ऐसा विशेषकर ग्राहकों से रकम हासिल करने के मामलों में दिखता है।

स्टॉकब्रोकरों की निगरानी बढ़ाने के लिए सेबी ने सितंबर 2016 में प्रोपराइटरी खाते के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए एक नियम जारी किया था और ब्रोकरेज को निर्देश दिया था कि वे प्रोपराइटरी खाते को ग्राहक खातों से अलग करें। सेबी ने कहा था कि दो तरह के खातों के बीच रकम के हस्तांतरण की अनुमति केवल विशेष परिस्थिति में ही होगी। उसने स्टॉक एक्सचेंजों को भी ब्रोकरों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि यदि ब्रोकर द्वारा तैयार आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट में अधिक अंतर दिखता हो तो आंतरिक अंकेक्षक को नए सिरे से नियुक्त करने पर गौर करना चाहिए।

लेकिन इन सब उपायों के बावजूद कई मामलों में देखा गया है कि ब्रोकर लगातार संबंधित पक्ष के लेनदेन करते रहे हैं क्योंकि यह प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के दायरे में नहीं आता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि ब्रोकरों ने किसी प्रकार प्रोपराइटरी ट्रेडिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहे।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान फेयरवेल्थ, बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स, गिनीज, कासा फिनवेस्ट, फिकस सिक्योरिटीज जैसे मामलों में देखा गया है कि ब्रोकरों के डिफॉल्ट के कारण निवेशकों और ग्राहकों को कैसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेबी ने इस स्थिति से निपटने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को एक ढांचा तैयार करने के लिए कहा है ताकि ग्राहकों के धन को ब्रोकरों के खुद के उद्यमों से सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार के मामलों को ध्यान में रखते हुए बाजार नियामक ने जून में नियमों को और सख्त बनाया था ताकि ब्रोकरों को रकम जुटाने के लिए ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखने से रोका जा सके। इसका उद्देश्य ग्राहकों के पावर ऑफ अटॉर्नी के इस्तेमाल से उनकी रकम को हड़पने की रोकथाम की जा सके। बाजार नियामक ने ग्राहकों के प्रतिभूति खातों को बंद करने के लिए समयसीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी लेकिन बाद में उसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था।

प्रॉक्सी सलाहकार फर्म आईआईएएस के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक (कंपनी प्रशासन) अमित टंडन ने कहा, 'सेबी की इस कार्रवाई से उस समुदाय को एक मजबूत संदेश गया है जो ग्राहकों की प्रतिभूतियों के उपयोग में नियमों की खामियों का फायदा उठा रहे थे। बड़े ब्रोकर सहित तमाम ब्रोकर लंबे समय से बिना किसी अधिकार के ग्राहकों की गिरवी का इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि निवेशकों की रकम के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह एक सही पहल है।'

हालांकि कार्वी ने फिलहाल डिफॉल्ट नहीं किया है और उसके प्रबंधन ने बैंकों को आश्वस्त किया है कि समूह के पास पर्याप्त रकम उपलब्ध है। लेकिन लेनदार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कार्वी समूह की कंपनियों में उनका 2,900 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश है। प्रतिभूति एवं अपील ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को सेबी को कार्वी की दलील सुनने और ग्राहकों के पावर ऑफ अटॉर्नी के इस्तेमाल पर राहत देने के लिए उसकी याचिका पर गौर करने के लिए कहा था क्योंकि इससे मौजूदा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सेबी ने अपने अदेश में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया।

मौजूदा ढांचा

- सेबी ग्राहकों की कुछ खास प्रतिभूतियों को फंड जुटाने के लिए बैंकों एवं एनबीएफसी के समक्ष गिरवी रखने से कारोबारी सदस्यों को रोकता है, भले ही उन्हें अधिकृत किया गया हो
- अगर ग्राहक ने प्रतिभूति के लिए पूर्ण भुगतान नहीं किया है तो बिना भुगतान वाले अलग ग्राहक प्रतिभूति खाते खोलने को कहता है
- कारोबारी सदस्यों की तरफ से खोले गए सभी मौजूदा ग्राहक प्रतिभूति खातों को बंद करने की जरूरत

एयर इंडिया में कई निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी

पृष्ठ 1 का शेष...

पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज मिलने के बावजूद एयर इंडिया की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'विकासशील देश होने के नाते कई ऐसे क्षेत्र और कंपनियां हैं जहां सरकार को अपने संसाधनों को निवेश करने की जरूरत है। ऐसे में मजबूत निजी कंपनी द्वारा विमानन कंपनी का संचालन सकारात्मक कदम है।'

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हो पाता है तो इसके बंद होने की आशंका है।

रोडशो के दौरान दिलचस्पी दिखाने वाले निवेशकों ने भारत में विमानन क्षेत्र के नियमों, एयर इंडिया के कर्ज भुगतान चक्र, पट्टे की नियम एवं शर्तों तथा कंपनी के स्वामित्व वाले विमानों के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही सरकार के क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) से जुड़े वित्तीय अवसरों के बारे में भी पूछताछ की गई।अधिकारी ने कहा, 'रोडशो में शामिल निवेशकों की इसमें दिलचस्पी थी और उन्हें इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी भी है। उनमें से कई ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे बिक्री प्रक्रिया को आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी।' उदाहरण के लिए सरकार के अधिकारी ने पुष्टि की कि एयर इंडिया के खाते से अतिरिक्त कर्ज के बोझ को कम करने की योजना है, जिनमें से 29,500 करोड़ रुपये को एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग कंपनी में डाला जा चुका है। करीब 15,000 करोड़ रुपये तक कर्ज और कम किया जा सकता है।

एयर इंडिया पर 31 मार्च तक 58,282.92 करोड़ रुपये का कर्ज था। इनमें से 29,464 करोड़ रुपये का कर्ज विशेष उद्देश्यीस इकाई के जरिये कम किया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्री के नेतृत्व में 7 सितंबर को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। पिछली बार विनिवेश प्रयास के दौरान संभावित बोलीदाताओं ने 33,992 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ उठाने में असमर्थता जताई थी, जिसकी वजह से इस कंपनी का अधिग्रहण करने कोई आगे नहीं आया।

रोडशो में शिरकत करने वाली एक कंपनी के कार्याधिकारी ने कहा, 'निवेश को कंपनी का कायाकल्प करने के लिए उचित मौका दिए जाने की जरूरत है। एयर इंडिया ने पिछले कई वर्षों के दौरान कार्यशील पूंजी के तौर पर अल्पावधि कर्ज लिए हैं जबकि घाटे की वजह से उसका नेटवर्थ ऋणात्मक हो गया है। सामान्य तौर पर निवेशक ऐसे कर्ज को लेने से परहेज करते हैं जिसका भुगतान सामान्य नकदी प्रवाह से करना संभव नहीं होता है।'

उन्होंने आगे कहा कि निजी मालिक होने से सॉवरिन गारंटी की सुविधा भी नहीं होगा जबकि अभी बैंकों को कर्ज पर सरकार से गारंटी मिल रही है। उक्त अधिकारी ने कहा, 'बैंक भी इस मामले में सतर्क हैं कि निजी कंपनी के खाते में ज्यादा कर्ज नहीं जाना चाहिए।'

सरकार ने एयर इंडिया, उसकी सहायक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए दिसंबर तक अभिरुचि पत्र मंगा सकती है लेकिन चालू वित्त वर्ष में विनिवेश प्रक्रिया पूरी करने की हड़बड़ी में नहीं है। सरकार ने पहले अक्टूबर में अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने की इच्छा जताई थी लेकिन अब शेयरधारक समझौता मसौदा लाने से इसमें देरी हो सकती है।

इस प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ एक अधिकारी ने कहा, 'महत्त्वपूर्ण यह है कि बिक्री प्रक्रिया सफल रहे और शेयरधारक समझौता पहले लाने से निवेशकों के बीच कर्मचारियों, शर्तों आदि को लेकर निश्चितता आएगी। पिछले साल कई निवेशकों ने ऐसे सवाल पूछे जिनके बारे में अभी हम जवाब नहीं दे सकते। इस बार वे अपने निवेश को लेकर शुरुआत से ही स्पष्ट हैं।'

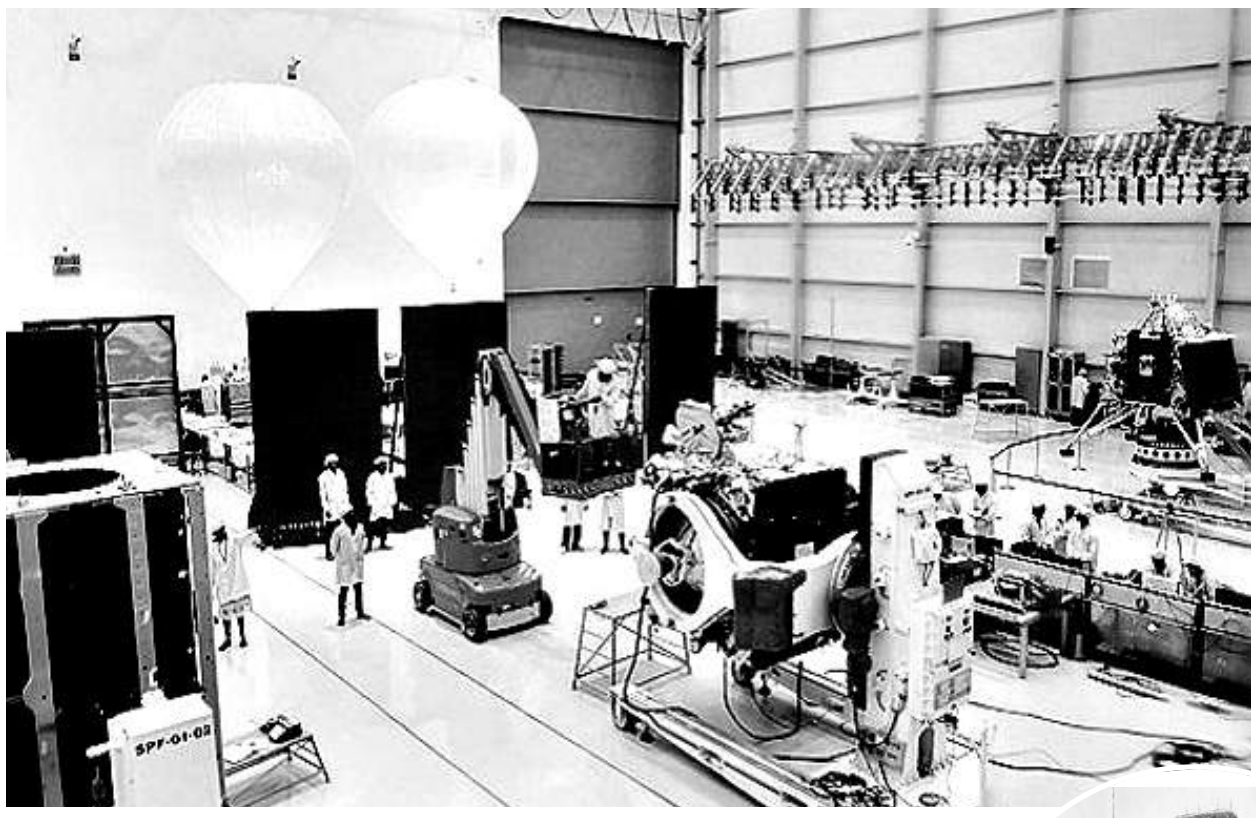

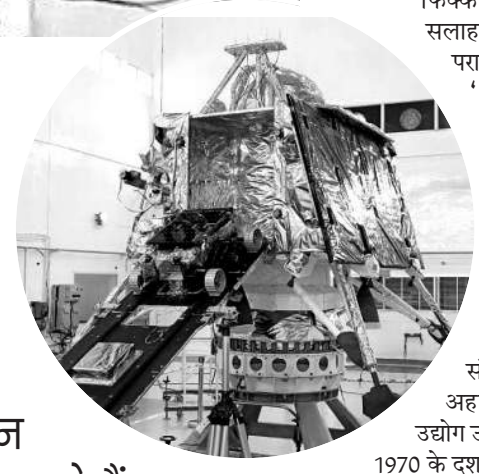

स्टार्टअप की अब अंतरिक्ष में उड़ान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बहुत से कर्मचारी वेतन के चेक का आराम त्याग रहे हैं और खुद की स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं

टी ई नरसिम्हन

भले ही उनका आकार छोटा है और उनके पास भरपूर नकदी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के अंतरिक्ष उद्योग में उत्साही उद्यमियों की कमी नहीं है। अंतरिक्ष उद्यमियों का मानना है कि इस क्षेत्र में संभावनाएं अपार हैं। उपग्रह सलाहकार यूरोकंसल्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का बाजार ही वर्ष 2027 तक 69 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अगले आठ वर्षों के दौरान दुनियाभर में 7,000 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण होने का अनुमान है। अगर इसमें अंतरिक्ष बाजार के अन्य हिस्सों को भी शामिल करते हैं तो पूरा उद्योग 350 अरब डॉलर का हो जाता है। इसमें भारत की हिस्सेदारी महज दो फीसदी है।

इस क्षेत्र में अपार अवसरों को देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बहुत से कर्मचारी आराम से वेतन मिलने का मोह त्याग रहे हैं और खुद के उपक्रम शुरू कर रहे हैं या अन्य स्टार्टअप से बतौर सलाहकार जुड़ रहे हैं। इन स्टार्टअप में से ज्यादातर उन तीन क्षेत्रों में शुरू हुए हैं, जिनमें भारतीय वैज्ञानिकों को बढ़त प्राप्त है। ये तीन क्षेत्र हैं- अंतरिक्ष से संबंधित हार्डवेयर और कलपुर्जों की डिजाइनिंग और विनिर्माण, अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा से संबंधित सेवाएं और अंतरिक्ष से संबंधित अन्य स्टार्टअप को परामर्श देना। इन स्टार्टअप के आंकड़े ही इनकी कहानी बयां करते हैं। तीन साल पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में महज 3-4 कंपनियां थीं, जिनकी तादाद आज 30 से अधिक हो गई है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 30 तक पहुंची

- छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का बाजार वर्ष 2027 तक 69 अरब डॉलर का होने का अनुमान
- अगले आठ वर्षों के दौरान दुनियाभर में 7,000 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण होने का अनुमान
- अंतरिक्ष बाजार के अन्य हिस्सों को भी शामिल किया जाए तो पूरा उद्योग 350 अरब डॉलर का
- इसरो के कर्मचारी खुद के उपक्रम शुरू कर रहे हैं या अन्य स्टार्टअप से बतौर सलाहकार जुड़ रहे हैं
- अंतरिक्ष क्षेत्र में 3 साल पहले तक 3-4 कंपनियां थीं, जिनकी तादाद आज 30 से अधिक हो गई
- इस क्षेत्र में वर्ष 2019 में अब तक 34 लाख डॉलर का निवेश आ चुका है

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व इंजीनियर और 2018 में स्काईरूट की स्थापना करने वाले पवन कुमार चांदना ने कहा, 'अंतरिक्ष के भविष्य में मेरी रुचि, मांग में बढ़ोतरी, वैश्विक अंतरिक्ष कारोबार में भारत को बढ़त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की जरूरत जैसी विभिन्न वजहों से मैंने नौकरी छोड़ी और खुद का उद्यम शुरू किया।'

स्काईरूट एयरोस्पेस के पास 35 लोगों की टीम है। इनमें से ज्यादातर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इसरो के पूर्व कर्मचारी हैं। यह टीम छोटे उपग्रहों के लिए लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही है। ये लॉन्च व्हीकल 200 से 720 किलोग्राम पेलोड क्षमता के हैं। ये लॉन्च व्हीकल उपग्रहों को किफायती लागत में पहुंचाने की पेशकश करते हैं। सैटश्योर के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी प्रदीप बसु ने कहा कि इसरो के कर्मचारियों के यह कंपनी बनाने से इसे साफ तौर पर फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि टीम को उद्योग के बारे में सभी जानकारियां हैं। सैटश्योर 2016 में शुरू हुई थी और आज इसके कार्यालय भारत, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हैं।

यह अपने कारोबारी ग्राहकों को बेसपोक जियोस्पेटियल बिग डेटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। यह प्लेटफॉर्म उपग्रह तस्वीरों, प्रपाइइटेरी एल्गोरिद्म को मौसम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन तस्वीरों, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों से जोड़ता है ताकि कृषि, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, बुनियादी ढांचा एवं जलवायु से संबंधित तात्कालिक और विशेष भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिल सके।

उदाहरण के लिए यह 1990 के दशक के उपलब्ध उपग्रह डेटा का इस्तेमाल कर सूखे, बाढ़ या कीटों के प्रकोप जैसे जोखिमों का आकलन कर सकता है और उन्हें कम करने के लिए कदम उठा सकता है। इसमें तात्कालिक सूचनाओं और शुरुआती चेतावनी संकेतों के सृजन के लिए जियोस्पेटियल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जहां स्टार्टअप होती हैं, वहां निवेशक भी आते हैं। वर्ष 2019 में ही अब तक इस क्षेत्र में 34 लाख डॉलर आ चुके हैं। ज्यादातर पैसा आईआईटी, ऐंजल निवेशकों, वेंचर कैपिटल, पीई जैसे इन्क्यूबेशन सेंटरों और धनी उद्यमियों से आया है। उदाहरण के लिए पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने कावा स्पेस में निवेश किया है। कावा स्पेस ऐसी स्टार्टअप है, जो वित्तीय सेवा कंपनियों, सरकारों आदि के लिए पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रहों की डिजाइनिंग एवं परिचालान करती है। यह पहले के अंतरिक्ष उद्योग की प्रकृति में बड़ा बदलाव है। पहले यह उद्योग क्लस्टरों में विकसित हुआ और केवल इसरो की जरूरत को लेकर बना, जो इसरो को उसके मिशनों के लिए कलपुर्जों की आपूर्ति करता है। इसके नतीजतन उद्योग सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों तक ही सीमित रहा।

फिक्की की अंतरिक्ष शाखा के पूर्व सलाहकार और एक अंतरिक्ष परामर्शदाता रतन श्रीवास्तव ने कहा, 'अब रॉकेटों, उपग्रहों, ऐप्लीकेशन और संबंधित जमीनी बुनियादी ढांचे की जरूरत में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में निजी उद्योग के लिए घरेलू बाजार को आपूर्ति और वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जुड़ने के लिए उत्साहजनक समय है।' पिक्सल लैब्स के संस्थापक और सीईओ अवैस अहमद ने कहा, 'आज अंतरिक्ष उद्योग उस जगह है, जहां कंप्यूटर उद्योग 1970 के दशक में था।' पिक्सल लैब्स नैनो-उपग्रहों के लिए कॉन्सटलेशन बनाती और प्रक्षेपित करती है। उन्होंने कहा, 'प्रक्षेपण की लागत में कमी आ रही है। अहम इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों का आकार छोटा होता जा रहा है और ऑफ-दी-सेल्फ उत्पादों से विनिर्माण की लागत घट रही है। यह स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक बाजार है।'

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कृषि और प्रदूषण निगरानी जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक को अपनाए जाने की भारी संभावनाएं हैं। आज बहुत सी कंपनियां अंतरिक्ष से संबंधित एवं उत्पाद खरीदना चाहती हैं। लेकिन इन स्टार्टअप में से कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंची है।

श्रीवास्तव ने कहा, 'इन स्टार्टअप में वृद्धि एवं स्थायित्व और वीसी मूल्यांकन को तर्कसंगत साबित करने के लिए लंबी अवधि की कारोबारी योजना विकसित करने को लेकर समस्याएं हैं।'

इस समय मांग अन्य कारोबारों से आती है। उन्होंने कहा कि इसरो भारतीय स्टार्टअप की बहुत अधिक सेवाएं नहीं लेता है। इसलिए यह कारोबारी मॉडल उद्योग की अन्य स्टार्टअप से राजस्व सृजित करने का है। उपग्रह स्टार्टअप को प्रक्षेपण स्टार्टअप की और प्रक्षेपण स्टार्टअप को उपग्रह स्टार्टअप की जरूरत है। उपग्रह कलपुर्जा विनिर्माताओं को उपग्रह ऑपरेटरों और उपग्रह ऑपरेटरों को उपग्रह कलपुर्जा विनिर्माताओं की जरूरत है।

इस उद्योग को वर्क-शेयर मॉडल से बाहर निकलकर भरा-पूरा निर्यातक बनने के लिए पहले कुछ चीजों में बदलाव करना होगा। श्रीवास्तव ने कहा, 'हमें अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। इस समय हमारे पास चालू स्पेस पोर्ट है, जहां से रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं।'

छोटे कारोबारियों के लिए

डिजिटल राह आसान बनाती `व्यापार'

रमणी रंजन महापात्र

एक छोटे कारोबारी परिवार से आने वाले सुमित अग्रवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि खातों का मिलान करना उनके पिता के लिए कितना श्रमसाध्य काम था। हालांकि छोटे कारोबारियों के लिए बनाए गए अकाउंटिंग ऐप 'व्यापार' की मदद से यह काम बहुत आसान हो गया है। अग्रवाल ने वर्ष 2015 में सह-संस्थापक शुभम के साथ इस फिन-टेक स्टार्टअप को शुरू किया था।

कंपनी छोटे उद्यमियों के लिए कारोबारी इनवॉइस, इन्वेंटरी, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) बिल और अकाउंटिंग जरूरतों को पूरा कर रही है। 'व्यापार' ने हाल ही में इंडिया मार्ट की अगुआई वाले सीरीज ए के दौर में 36 करोड़ रुपये जुटाए हैं। हालिया निवेशक एग्जिलॉर वेंचर्स और इंडिया क्वोशंट ने भी इस दौर में हिस्सा लिया था। बीएसआईटी बेंगलूरु से स्नातक करने के बाद अग्रवाल ने इंट्यूइट के 'क्विक बुक' उत्पाद के साथ 8 वर्ष तक काम किया लेकिन वह भारतीय बाजार के लिए ऑफलाइन उपाय विकसित करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया। एक दिन उनके परिवार के एक सदस्य ने पूछा कि क्या वह ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे मोबाइल पर वित्तीय लेखा-जोखा का प्रबंधन आसानी से किया जा सके?

> ऐप ने अकाउंटिंग को काफी आसान बना दिया है। साधारण गणना के लिए ऐप का मोबाइल वर्जन मुफ्त है हालांकि प्रीमियम ग्राहकों को भुगतान करना होता है

अग्रवाल कहते हैं, 'उन्हें बिल और आमदनी का प्रबंधन करने के लिए इसकी जरूरत थी। हमारा उद्देश्य लाखों डॉलर की कंपनी बनाना नहीं बल्कि इस समस्या का समाधान करना था।' उन्होंने दिसंबर 2015 में अपना उत्पाद लॉन्च किया। अप्रैल 2016 में जब उन्होंने 'व्यापार' पर पूरा ध्यान देने के लिए स्टार्टअप की नौकरी छोड़ दी, तब तक वह रोजाना 150 डाउनलोड तक पहुंच चुका था। बी2बी स्टार्टअप ने इसके बाद डेस्कटॉप वर्जन भी लॉन्च किया और अपनी टीम की क्षमता को बढ़ाया।

व्यापार के सह-संस्थापक सुमित अग्रवाल कहते हैं, 'हमने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने की योजना बनाई। हम जल्द ही सबसे बड़ा कारोबारी अकाउंटिंग उपाय होंगे।' वह बताते हैं, 'मैं मार्च 2017 तक अपनी बचत से स्टार्टअप को चला रहा था और इसके बाद हमने उत्पाद के साथ शुल्क लेना शुरू किया।' जुलाई 2017 में जीएसटी आने के बाद ऐप डाउनलोड करने की संख्या तेजी से बढ़ी। वर्तमान में इसके 10 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.6 रेंटिंग मिली है। इसका सामान्य मोबाइल वर्जन मुफ्त है जिससे साधारण गणना की जा सकती है लेकिन प्रीमियम सबस्क्राइबर अपने टैरिफ प्लान के हिसाब से भुगतान करते हैं। डेस्कटॉप वर्जन का शुल्क 2,499 रुपये से लेकर 10,999 रुपये तक है जिसके साथ एक माह का मुफ्त एक्सेस भी दिया जाता है। खबरों के अनुसार कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 1.4 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है।

भारत में छोटे कारोबारी अभी भी पेपर पर बिल बनाते हैं और इसे खातों में लिखकर खुद पूरी गणना करते हैं। इससे न सिर्फ समय खर्च होता है बल्कि गलती होनी की संभावना भी होती है। अग्रवाल के अनुसार, 'उपाय बिल्कुल आसान होना चाहिए। अकाउंटिंग की जानकारी नहीं रखने वाला व्यक्ति भी व्यापार का उपयोग आसानी से कर सकता है।' वह कहते हैं कि सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा संगठित क्षेत्र में आएगा।

इंडियामार्ट ने 'व्यापार' में निवेश को बड़ी संभावना के तौर पर देखा। इंडियामार्ट के प्रबंध निदेशक दिनेश अग्रवाल कहते हैं, 'यह निवेश हमारे दीर्घावधि लक्ष्यों का हिस्सा है, जिसके तहत लाखों कारोबारियों को तकनीक समर्थित आसान और कम कीमत वाले उपाय उपलब्ध कराने से कारोबार को आसान बनाया जाना है।' व्यापार के संस्थापक का कहना है कि इस क्षेत्र में इंडियामार्ट की विशेषज्ञता से कंपनी को अपने ग्राहक बढ़ाने में आसानी होगी।

वेतन का एक हिस्सा लेकर प्रशिक्षण देने वाली स्टार्टअप का चलन

कंपनी आपको कोर्स कराने के लिए पैसे के साथ अच्छे वेतन वाली नौकरी देने की गारंटी देगी फिर कोर्स की राशि को कम ब्याज दर पर आपके वेतन से काटेगी

टी ई नरसिम्हन

माना कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फीस के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। ऐसे में कोई कंपनी न केवल फीस भरने बल्कि अच्छे वेतन की नौकरी लगवाने की भी गारंटी देती है। यह कंपनी आपके वेतन में से फीस की उस राशि की कटौती करती है और मामूली ब्याज वसूलती है।

दरअसल अब ऐसा भारत में हो रहा है। ऐसी कंपनियों को लेकर ग्राहकों और निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। इसे आय साझा समझौता (आईएसए) शिक्षा मॉडल नाम दिया गया है। छात्र नौकरी मिलने तक उच्च शिक्षा की फीस को वापस लौटाने को टाल सकते हैं। यह मॉडल अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। भारत में भी इस क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्टार्टअप मौजूद हैं, जो अभी केवल पेशेवरों को नए कौशल मुहैया कराने पर ध्यान दे रही हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलरेटेड लर्निंग (एसओएएल) के सह-संस्थापक प्रतीक अग्रवाल ने कहा, 'आईएसए कॉलेज डिग्री की फीस भरने के सबसे उत्साहजनक नवोन्मेष के रूप में उभरा है।'

आईएसए मॉडल

- इसे आय साझा समझौता (आईएसए) शिक्षा मॉडल नाम दिया गया है
- छात्र नौकरी मिलने तक फीस को वापस लौटाने से टाल सकते हैं
- यह मॉडल अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है
- भारत में भी इस क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्टार्टअप मौजूद हैं
- यह फिलहाल केवल पेशेवरों को नए कौशल मुहैया कराने पर ध्यान दे रही हैं
- स्टार्टअप फ्रेशर और इंजीनियरिंग स्नातकों को नए कौशल देने के लिए फीस का भुगतान करती हैं

कैसे करता है काम

इस अनुबंध के तहत छात्र को विद्यार्थी ऋण लेने के बजाय अपने भविष्य की आय का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक चुकाना होता है। ये स्टार्टअप फ्रेशर और इंजीनियरिंग स्नातकों को नए कौशल देने के लिए फीस का भुगतान करती हैं। इस साल अनुमान लगाया गया था कि भारत में कॉलेज शिक्षा के बाद कौशल मुहैया कराने का बाजार 37 करोड़ डॉलर (26,300 करोड़ रुपये) और कॉलेज के बाद तकनीकी कौशल का बाजार 18 करोड़ डॉलर का है। यह बाजार हर साल करीब 50 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। हर साल करीब 90 लाख छात्र कॉलेजों से स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन 85 फीसदी को अच्छी और व्हाइट कॉलर नौकरी नहीं मिल पाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिष्ठित तकनीकी कंपनियां सभी बीई/बीटेक स्नातकों में से आधे छात्रों और 60 फीसदी एमबीए डिग्रीधारियों को भर्ती करने योग्य नहीं मानती हैं।

एटेनयू के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी दिव्यम गोयल ने कहा, ' आईएसए मॉडल अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मददगार है। हमारे 80 फीसदी छात्र अपने परिवारों पर निर्भर हैं और परिवार की आय सालाना 5 लाख रुपये से कम है।' गोयल का दावा है कि उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पांच बैचों में 500 से अधिक छात्र नामांकित हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में छात्रों को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहला बैच स्नातक होने जा रहा है और उनमें से 40 फीसदी को प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिल चुके हैं।

वित्तीय तकनीक के अवसरों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए यह खंड बढ़ने और इसमें निवेशकों की रुचि बढ़ने की संभावना है। वित्तीय तकनीक कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आईएसए के साथ गठजोड़ कर रही हैं।

पेस्टो टेक का कहना है कि वह यह भरोसा देती है कि अगर वह छात्र को कम से कम सालाना 15 लाख रुपये की नौकरी नहीं दिला पाई तो इसका मतलब है कि उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छा नहीं था और छात्र को उसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर ध्यान दे रही है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों में नौकरी हासिल कर सकें। इसके कार्यक्रमों में छात्र को तीन साल के लिए 17 फीसदी वेतन साझा करना पड़ता है। इंटरव्यूबिट एक अलग मॉडल पर काम करती है। इसके पूर्व भुगतान मॉडल में छात्र को छह महीने के कोर्स के लिए 2 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है, जिसमें नौकरी की गारंटी दी जाती है। एक बाद में भुगतान का मॉडल भी है। इसमें अगर छात्र को सीटीसी (कोस्ट टू कंपनी) की न्यूनतम गारंटी से अधिक वेतन की नौकरी मिलती है तो उसे अपने मूल वेतन का 17 फीसदी भुगतान करना पड़ता है। कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि छात्र को अधिकतम 3 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता है। नोवा सेमिता का कहना है कि इसी तरह निवेशको को फायदा तब होता है, जब उनकी स्टार्टअप का आकार बढ़ता है। आईएसए स्टार्टअप को तब फायदा मिलता है, जब छात्रों का करियर बढ़ता है। कंपनी ने कहा, 'हम आपके लिए संसाधनों में निवेश करते हैं और जोखिम खुद पर लेते हैं। इसके बदले हम आपको सालाना वेतन पांच लाख रुपये से अधिक मिलने पर आपकी आमदनी का 12 फीसदी तीन साल तक लेते हैं। अगर हम आपको इतने वेतन की नौकरी नहीं दिला पाते हैं तो आपको हमें कुछ नहीं देने की जरूरत है।'

निवेशकों को कैसे होता है फायदा

वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से एसओएएल, पेस्टो, इंटरव्यू बिट एकेडमी और मसाई स्कूल ने मैट्रिक्स पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल, एस्ट्रैक वेंचर्स, इंडिया क्वोशंट और अन्य से 40 लाख डॉलर से अधिक जुटाए हैं। ऐंजल निवेशकों में गूगल इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक शैलेश राव, इनटूइट इंडिया के पूर्व प्रमुख निखिल रूंगटा, स्नैपमिंट के संस्थापक अनिल गेलरा और क्रेडएक्स और लेट्स वेंचर्स के संस्थापक मनीष कुमार शामिल हैं।

एसओएएल के अग्रवाल का कहना है कि आईएसए मॉडल भारत में अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन इसमें भारी संभावनाएं हैं। ऐसी बहुत सी युवा आबादी है, जो अध्ययन जारी रखकर अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाती रहती है। लेकिन उसके लिए पैसे की कमी अड़चन बनती है। निखिल रूंगटा ने कहा, 'हर साल उत्तीर्ण होने वाले 60 फीसदी इंजीनियरिंग छात्र या तो बेरोजगार रहते हैं या अन्य अपने क्षेत्र से इतर कोई काम करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों पर विचार करते हैं तो यह समस्या 10 गुना बढ़ जाती है।'

अग्रवाल और गोयल का कहना है कि उनकी चुनौतियों मे फीस लौटाना सुनिश्चित करना है। एक चुनौती यह भी है कि कानूनी विवाद पैदा होने से यह कारोबार पटरी से उतर सकता है। इसके अलावा अधिक संख्या में अच्छी नौकरियां दिलाना भी स्टार्टअप की जिम्मेदारी बन जाता है क्योंकि ऐसा होने पर उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि वापस आएगी। इस कारोबार में भरोसा बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसे सफल बनाने के लिए गुणवत्ता आवश्यक है।

अटेनयू का कहना है कि वह कड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है और अपने 30 सप्ताह के कोर्स के लिए आने वाले कुल आवेदनों में से महज 1.4 फीसदी को चुनती है। एसओएएल ने अब तक आए 1,100 आवेदनों में से केवल 10 फीसदी को नामांकित किया है। अग्रवाल ने कहा, 'यह ऐसी असीमित फीस नहीं है, जो छात्र को चुकानी होती है। लोग 4-7 लाख रुपये में से विभिन्न राशियों की सीमा तय करते हैं।'

ये कंपनियां विभिन्न राजस्व मॉडलों को अपनाती हैं। कुछ एक से अधिक मॉडलों पर प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'आईएसए के जरिये संस्थान मेधावी छात्रों को प्रवेश दे पाते हैं, अन्यथा जिनके लिए कोर्स की फीस का भार वहन करना मुमकिन नहीं है। इस ऋण ढांचे में संस्थान शामिल हैं और अच्छी प्लेसमेंट का वादा करता है... इससे सुरक्षा की एक अन्य परत तैयार हो जाती है।'

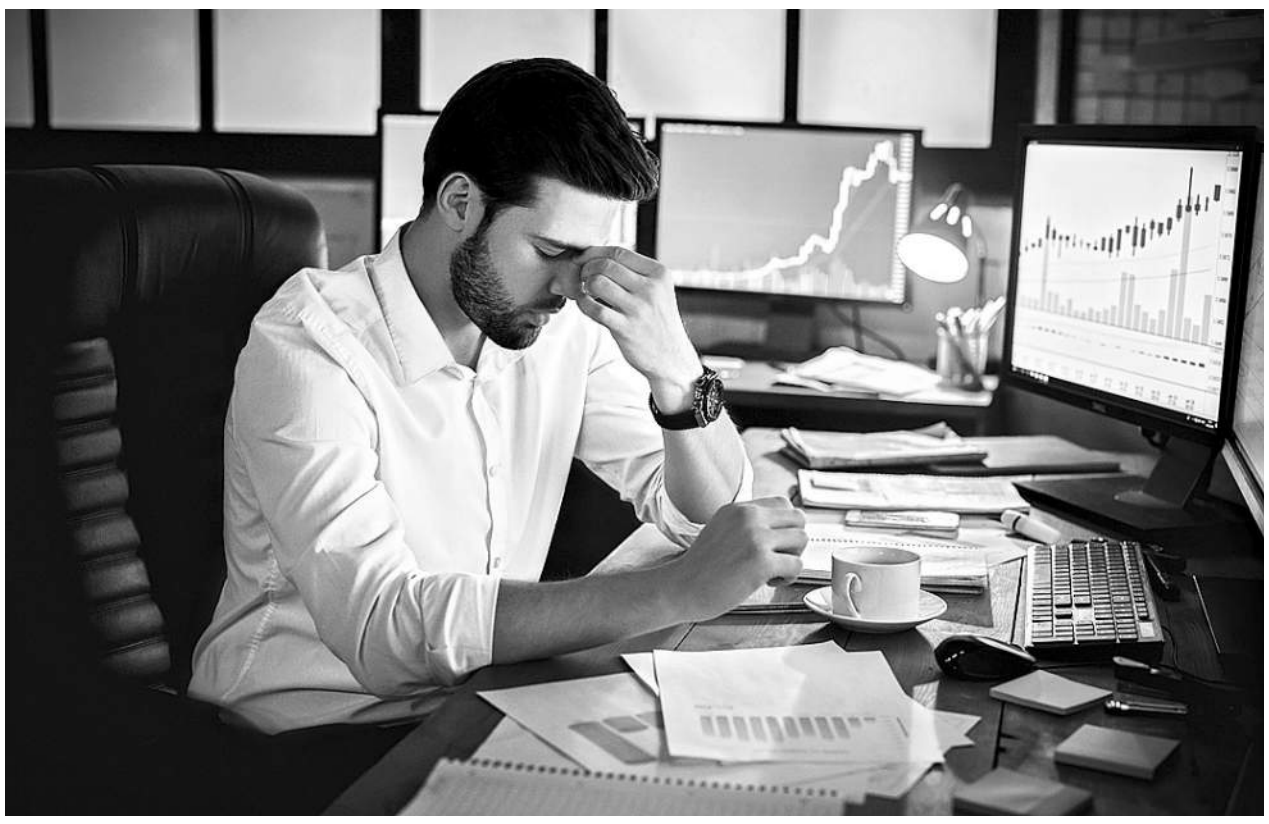

कार्वी संकट: डीमैट खातों में पड़े शेयरों का क्या करें

अगर डीमैट में पड़े शेयर जस के तस हैं तो कार्वी के क्लाइंट के पास किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाने का विकल्प है। अगर उनके शेयरों में हेराफेरी हुई है तो उन्हें फौरन शिकायत करनी चाहिए

संजय कुमार सिंह

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 22 नवंबर के इकतरफा आदेश में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को नए क्लाइंट यानी ग्राहक लेने से रोक दिया। इतना ही नहीं सेबी ने ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों के डीमैट खातों में मौजूद शेयर निकालने से भी प्रतिबंधित कर दिया। यह आदेश आते ही कार्वी के ग्राहकों में खलबली मच गई और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनके शेयरों का दुरुपयोग न हो गया और उन्हें घाटा नहीं झेलना पड़ा हो। इस आदेश का एक असर यह भी हुआ कि ग्राहकों के लिए शेयरों के सौदे करना मुश्किल हो गया और उन्हें असुविधाओं से दोचार होना पड़ा।

क्या करें कार्वी के ग्राहक?

- डिपॉजिटरी से हाल ही में आए अपने खाते के ब्योरे को जांचिए और देखिए कि आपने जो भी शेयर खरीदे हैं, वे आपके खाते में आ गए हैं या नहीं
- कार्वी से अपने डीमैट खाते में पिछले तीन साल में हुए हरेक लेनदेन का ब्योरा मांगिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके डीमैट खाते में आपकी अनुमति के बगैर कोई अनधिकृत लेनदेन तो नहीं हुआ है
- कार्वी से बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे ब्रोकर के पास डीमैट खाता खुलवाइए और उससे क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट (सीएमआर) ले लीजिए
- कार्वी के पास खाते को बंद करने और शेयर नए ब्रोकर के पास भेजने की अर्जी डालिए और साथ में सीएमआर की प्रति भी लगा दीजिए
- आप जितना मान रहे थे, आपके खाते में उससे कम शेयर हैं तो आपको सेबी से उसकी स्कोर्स वेबसाइट पर शिकायत करनी चाहिए और एक शिकायत एनएसई से भी करनी चाहिए

क्या है मामला

सेबी ने जो अंतरिम आदेश जारी किया, उसे पढ़ने से पता चलता है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने ग्रहाकों के शेयर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास गिरवी रखकर पैसा उठा लिया था। दिल्ली की डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म एसएएस ऑनलाइन के संस्थापक श्रेय जैन बताते हैं, 'जून के अपने परिपत्र के जरिये सेबी ने ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।'

जब कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर के पास डीमैट खाता खोलता है तो वह सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी हस्ताक्षर करता है। जब भी वह शेयर बेचने का आदेश देता है तो उसके डीमैट खाते से शेयर दो तरीकों से निकाले जा सकते हैं। पहले तरीके में वह डिलिवरी के निर्देश वाली पर्ची पर दस्तखत कर सकता है और उसे ब्रोकर को सौंप सकता है। लेकिन यह तरीका बहुत सुस्त और मुश्किल भरा होता है। इसीलिए ग्राहक दूसरा तरीका अपनाता है और सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकरों के सुपुर्द कर देता है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये ब्रोकर को ग्राहक के डीमैट खाते से शेयर निकालने और एक्सचेंज के सुपुर्द करने का अधिकार मिल जाता है। सेबी के आदेश की बात करें तो शायद कार्वी ने पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग किया था और ग्राहकों के खातों से शेयर निकाल लिए थे। शेयरों को गिरवी रखकर जो रकम जुटाई गई थी, वह ब्रोकर ने अपने बैंक खाते में डाल ली थी। सेबी के नियमानुसार ब्रोकरों को अपने सभी बैंक और डीमैट खातों का ब्योरा भी देना होता है, जो कार्वी ने नहीं किया। ग्राहकों के शेयर बेचकर जो भी रकम आई थी, वह शायद एक रियल एस्टेट फर्म को दे दी गई है।

सेबी का आदेश कहता है कि कार्वी ग्राहकों की ओर से सौदे करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इससे ग्राहकों को झटका लगा है। उनमें से कई को शेयर बेचने के लिए ब्रोकर को डिलिवरी वाली पर्ची भरकर देनी पड़ेगी, जो बेहद झंझट भरा काम है।

क्या करें ग्राहक

ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डीमैट खाते में रखे हुए शेयर जस के तस बने रहें। जैन की सलाह है, 'डिपॉजिटरी से हर महीने आपके पास डीमैट खाते की जो एकमुश्त रिपोर्ट आती है, उस पर गौर करें।' आपने जो भी स्टॉक खरीदे हैं, यदि वे सभी स्टॉक रिपोर्ट में नजर आते हैं तो आपको इस बात पर नजर दौड़ानी चाहिए कि किसी ने अनधिकृत तरीके से लेनदेन तो नहीं किया है। कार्वी से अपने डीमैट खाते में पिछले तीन साल में हुए लेनदेन का ब्योरा मांगें। यदि शेयर खाते से निकले हैं या खाते में जुड़े हैं तो ब्योरे में आपको नजर आ ही जाएगा। फायर्स के मुख्य कार्य अधिकारी और संस्थापक तेजस खोड़े का मशविरा काम का है। वह कहते हैं, 'अपने ट्रेडिंग खाते में बेकार पड़ी रकम फौरन निकाल लीजिए।' अब किसी और ब्रोकर के पास जाइए, खाता खोलिए और उससे क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट मांगिए। इस रिपोर्ट की एक प्रति कार्वी के पास भेज दीजिए और उससे खाता बंद करने तथा उसमें मौजूद शेयर आदि नए ब्रोकर के पास भेजने को कहिए। जीरोधा में परिचालन प्रमुख वेणु माधव कहते हैं, 'अगर आप अपने शेयर एक डीमैट खाते से दूसरे डीमैट खाते में भेजते हैं तो आपको 3 से 10 आधार अंकों का लेनदेन शुल्क चुकाना पड़ेग। लेकिन यदि आप शेयर दूसरे खाते में भेजकर पहला खाता बंद कर देते हैं तो ब्रोकर आपसे कोई शुल्क नहीं वसूल सकता।' ऐसे लेनदेन पर ग्राहक से पूंजीगत लाभ कर भी नहीं लिया जा सकता।

डीमैट खाते पर पड़ा असर

यदि आपको कोई शिकायत है तो सेबी की स्कोर्स (सेबी कंप्लेंट रीड्रेस सिस्टम) वेबसाइट पर जाकर उसे दर्ज कराएं। यदि आपके डीमैट खाते में पड़े शेयरों का दुरुपयोग किया गया है तो डिपॉजिटरी में भी शिकायत करें। आपने जो शेयर खरीदे थे, अगर वे आपके डीमैट खाते में नहीं भेजे गए हैं तो नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से शिकायत करें।

कार्वी के अधिकारियों ने कहा है कि वे ग्राहकों की रकम चुकाने के लिए शेयर बेच रहे हैं। अगर कंपनी रकम नहीं चुका पाती है तो निवेशकों को एक्सचेंज के पास चल रहे निवेशक सुरक्षा कोष से रकम (डिफॉल्ट करने वाले या निकाले गए प्रत्येक सदस्य के नाम पर 25 लाख रुपये प्रति निवेशक तक) दी जा सकती है।

शेयरों पर रखें नजर

आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पता ब्रोकर और डिपॉजिटरी के पास रहना चाहिए। यदि आप इनमें किसी तरह की तब्दीली कर रहे हैं तो उसकी सूचना भी ब्रोकर और डिपॉजिटरी को दी जानी चाहिए। जब भी कोई लेनदेन होता है तो संबंधित डिपॉजिटरी आपको एसएमएस के जरिये संदेश भेजती है। संदेश तुरंत पढ़ें ताकि आपके डीमैट खाते में हो रही गतिविधियों पर आपकी नजर रहे। इसी तरह ब्रोकर द्वारा भेज जा रहे सौदे के नोट और डिपॉजिटरी द्वारा हर महीने भेजे जा रहे खाते के विवरण पर भी नजर दौड़ाएं। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के कार्यकारी निदेशक विवेक सिंहानिया आगाह करते हैं, 'जो निवेशक निष्क्रिय पड़े रहते हैं और अपने खातों पर नजर नहीं रखते हैं, उनके साथ धोखा होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है।' वह यह भी कहते हैं कि सीडीएसएल में खाते वाले ग्राहक अपने डीमैट खाते में मौजूद शेयर देखने के लिए ईजी (इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टु सिक्योरिटीज इन्फॉर्मेशन) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनका अब ट्रेडिंग करने का इरादा ही नहीं है, उन्हें अपने ब्रोकर के पास अर्जी देकर अपने डीमैट खातों को फ्रीज करा देना चाहिए।

अंत में गड़बड़ का संकेत देने वाली कुछ घटनाओं पर नजर रखें। ये घटनाएं हैं – भुगतान में देर होना या ब्रोकर द्वारा तिमाही निपटान नहीं किया जाना यानी अपने पास पड़ी ग्राहकों की रकम नहीं लौटाया जाना। यदि सोशल मीडिया पर आपके ब्रोकर के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग जाए तो भी आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। जब आप कोई ऑर्डर देते हैं और आपको बार-बार संदेश मिलता है कि ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपके ब्रोकर को रिस्क रिडक्शन मोड पर डाल दिया गया है तब भी आप खबरदार हो जाएं क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ब्रोकर एक्सचेंज में 85 फीसदी मार्जिन इस्तेमाल की अपनी सीमा तक पहुंच चुका है।

डेट फंडों की परिसंपत्ति घटे तो फौरन पड़ताल करें

संजय कुमार सिंह

डेट म्युचुअल फंडों के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सितंबर में दो कंपनियों अल्टिको कैपिटल और रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स (आरबीबीएनएच) अपने बॉन्ड पर ग्राहकों को भुगतान नहीं कर पाईं, जिससे फंड कंपनियों पर संकट और भी गहराता दिखा। इसकी वजह यह है कि फंड कंपनियों ने इन दोनों इकाइयों में मोटा निवेश किया था। अल्टिको कैपिटल के बॉन्ड में कंपनियों के 537.67 करोड़ रुपये और आरबीबीएनएच एवं इससे संबद्ध कंपनियों के बॉन्ड में 947.37 करोड़ रुपये लगे थे। डिफॉल्ट और रेटिंग में गिरावट के कारण इन बॉन्ड में रकम लगाने वाले फंडों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में ठीकठाक कमी आई है। अल्टिको कैपिटल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो रियल एस्टेट में जमकर निवेश करने का खमियाजा भुगत रही है। आरबीबीएनएच मोटे कर्ज बोझ से जूझ रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों को डेट फंडों के मामले में समय अवधि पर आधारित सरल निवेश ढांचे पर चलना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार डेट फंडों की प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए एक अवधि तय करनी चाहिए। अगर निवेश अवधि छोटी है तो लिक्विड, अल्ट्रा-शॉर्ट या कम अवधि के फंडों में निवेश करें। रेडवुड रिसर्च की सह-संस्थापक विद्या बाला का सुझाव है, 'एक साल की समय अवधि वाले निवेशकों को क्रेडिट रिस्क या मध्यम अवधि के फंडों में निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी योजनाओं के साथ साख से जुड़े जोखिम होते हैं और इनमें कम तरलता वाले बॉन्ड रखे जाते हैं।' ऐसे फंडों के लिए तीन साल या इससे अधिक समय लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर इन फंडों पर क्रेडिट डिफॉल्ट का जोखिम आता है तब भी निवेशक इनमें निवेश बनाए रख सकते हैं और आने वाले समय में अपना प्रतिफल सुधरने तक इंतजार कर सकते हैं या बकाया रकम की वसूली से लाभ (डीएचएफएल और एस्सेल म्युचुअल फंडों को रकम लौटा चुकी हैं) ले सकते हैं। भुगतान में चूक की हालिया घटनाओं का असर निश्चित परिपक्वता अवधि वाली कई योजनाओं (एफएमपी) पर भी पड़ा है। क्लोज्ड एंड फंड अगर लंबी अवधि के हैं तो उन्हें दूर से ही नमस्ते कर देना चाहिए। बाला कहती हैं, 'निवेशकों के पास उन योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए, जिनमें थोड़ा सा भी जोखिम होता है।' एफएमपी सावधि जमा (एफडी) की तरह सुरक्षित नहीं होते हैं। जो लोग एक या दो साल के एफएमपी में निवेश करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी योजना केवल एएए-रेटिंग प्राप्त या सरकारी बॉन्ड में निवेश करती हो। कई फंड कंपनियों ने हाल में भुगतान में चूक के बाद कमजोर योजनाओं को अलग करना (साइडपॉकेटिंग) शुरू कर दिया है। साइडपॉकेटिंग के जरिये खराब प्रदर्शन करने वाली योजनाओं को एक अलग पोर्टफोलियो में रखने से मुख्य पोर्टफोलियो से निकासी का जोखिम कम हो जाता है।

ऐसे फंडों में बने रहने का निर्णय दो बातों पर निर्भर करता है। अगर आपको रकम की जरूरत है तो नुकसान कम करें और बाहर निकल जाएं। अगर निवेश बनाए रखने का निर्णय लेते हैं तो मुख्य पोर्टफोलियो में खराब गुणवत्ता वाली योजनाएं नहीं रहने दें। कुछ सलाहकार अपने क्लाइंट को बड़े आकार के फंड में निवेश करने ही सलाह देते हैं।

> निवेशकों को डेट फंडों के मामले में एक सरल समय अवधि वाले निवेश ढांचे का पालन करना चाहिए

पर्सनलफाइनैंस प्लान के संस्थापक दीपेश राघव कहते हैं, 'बड़े आकार के फंड ऐसी चीजों से कम प्रभावित होते हैं।' विभिन्न जगह निवेश करने वाला एक कुशल फंड भुगतान में एकाध चूक से प्रभावित नहीं होता है। इतना ही नहीं, जब एक छोटे फंड में भुगतान में चूक होती है और फंड प्रबंधक पर निकासी का दबाव बढ़ता है तो उच्च गुणवत्ता वाली योजनाएं बेचनी पड़ती हैं। इससे पोर्टफोलियो में खराब गुणवत्ता वाली योजनाओं की संख्या बढ़ जाती है। डेट फंडों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में तेजी से गिरावट के मद्देनजर निवेश रोक दें और आगे की पड़ताल शुरू कर दें।

पोर्टफोलियो की गुणवत्ता जांचने और इसमें तब्दीली करने के लिए किसी सलाहकार की मदद ले सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला पोर्टफोलियो वह होता है, जिसका एए+ और एएए+ बॉन्ड में निवेश होता है। इसके अलावा केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर आंख मूंद कर निवेश नहीं करें क्योंकि हो सकता है कि पूर्व में अधिक साख या ब्याज दर जोखिम वाली योजनाओं में निवेश करने से बेहतर प्रतिफल मिला होगा। सेवानिवृत्त लोग, जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो पर निर्भर हैं, उन्हें डेट फंडों में अधिक जोखिम वाली योजनाओं से पूरी तरह बचना चाहिए। निचले कर दायरे में आने वाले लोगों के लिए एफडी के साथ बने रहना अच्छा होगा।

अपने फास्टैग को प्रीपेड कार्ड से जोड़ें बचत या चालू खाते से नहीं

वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य होने वाला है। अगर फास्टैग को अपने जमा खाते से जोड़ देंगे तो टोल की रकम सीधे आपके बैंक खाते से कटने लगेगी

बिंदिशा सारंग

अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में ऐसा क्या था, जो अभी तक भारत में नहीं था और इसी महीने जिसकी शुरुआत की जा रही है? जवाब है फास्टैग। यह नाम आपने नहीं सुना हो यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यह शब्द खासा चर्चा में रहा है। देर से ही सही मगर 15 दिसंबर को भारत भी उन 40 से ज्यादा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली काम कर रही है और यह प्रणाली फास्टैग पर ही काम करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी (आरएफआईडी)कार्ड के जरिये टोल संग्रह की इस प्रणाली में शामिल तकनीक को ही फास्टैग का नाम दिया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल बैंकिंग के प्रमुख शैलेंद्र सिंह बताते हैं, 'इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए बने इस कार्ड में बार-बार रकम डाली जा सकती है और आपको यह कार्ड अपनी कार की विंडस्क्रीन यानी आगे वाले शीशे पर चिपकाना होता है। इसके बाद आपको टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ता, जिससे वाहनों की आवाजाही आसान हो जाती है।'

सरकार फास्टैग के मुद्दे पर इतनी गंभीर है कि जो लोग फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनसे दोगुना टोल वसूला जाएगा। जाहिर है कि आपके लिए भी अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है तो आपको इससे जुड़े कुछ जरूरी पहलू समझ लेने चाहिए।

फास्टैग से संबंधित कुछ सवाल-जवाब

1. मुझे अपने दोपहिया के लिए फास्टैग चाहिए?

नहीं आपको नहीं मिल सकता

2. मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं?

टैग हटा दीजिए और खाता बंद कर दीजिए

3. मेरे पास दो कार हैं?

दोनों के लिए अलग-अलग फास्टैग लीजिए

4. मेरे खाते से गलत रकम कट गई है या उस पर विवाद है?

बैंक के कॉल सेंटर से संपर्क कीजिए

5. मैं टोल प्लाजा के आसपास 10 किमी के दायरे में रहता हूं?

फास्टैग खरीदिए, दस्तावेज जमा कीजिए और छूट ले लीजिए

6. फास्टैग में रकम है पर टोल प्लाजा पर काम नहीं कर रहा?

नकद टोल चुका दीजिए और अपने बैंक से संपर्क कीजिए

फास्टैग खरीदना काफी हद तक प्रीपेड सिम खरीदने जैसा ही होता है। फास्टैग भेजने वाले पॉइंट ऑफ सेल पर पहुंचिए, अपने ग्राहक को जानिए यानी केवाईसी से जुड़े दस्तावेज और अपने वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जमा कीजिए, आवेदन पत्र भरिए और टैग एक्टिवेट यानी चालू कर लीजिए। सिम कार्ड आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डालना होता है, लेकिन फास्टैग आपको कार पर चिपकाना पड़ता है। जब भी आप किसी टोल प्लाजा से गुजरेंगे, टोल शुल्क आपके फास्टैग खाते में मौजूद राशि से खुद-ब-खुद कट जाएगा।

जिस तरह सिम कार्ड को आप बार-बार रीचार्ज कराते हैं, उसी तरह अगर आपका फास्टैग प्रीपेड खाते से जुड़ा है तो आपको उसे भी रीचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आप फास्टैग को बचत या चालू खाते से जोड़ लेते हैं तो टोल शुल्क आपके खाते में मौजूद रकम से कट जाएगा।

आईसीआईसीआई बैंक में असुरक्षित संपत्तियों के प्रमुख सुदीप रॉय बताते हैं, 'ग्राहक जब भी अपने फास्टैग खाते में कोई लेनदेन करते हैं यानी रकम जोड़ते हैं या टोल कटता है तो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर फौरन टेक्स्ट अलर्ट आता है। बैंकों के डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर किसी भी समय फास्टैग में रकम लोड की जा सकती है।'

कई बैंक पहले ही फास्टैग से जुड़ चुके हैं जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक। इसके अलावा विभिन्न बैंकों तथा इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए गए 28,500 से भी ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल पर भी ये फास्टैग मिल रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और पेट्रोल पंपों पर भी बनाए गए हैं।

सिंह बताते हैं, 'फास्टैग का खाते और बैंक से कोई मतलब नहीं होता।' इसका मतलब है कि आपको टैग लेने के लिए उस बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, जहां पहले से ही आपका खाता है या जहां से आपने कर्ज लिया है। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर जाएं। वहां आपसे एकबारगी जमा राशि ली जाएगी, जो 200 रुपये (कार, जीप और वैन के लिए) से शुरू होती है। इसके साथ ही आपको कम से कम 100 रुपये का रीचार्ज भी करना होगा। टैग पांच साल के लिए वैध होता है। कार, जीप और वैन मालिकों के फास्टैग में कम से कम 160 रुपये रहने चाहिए।

चूंकि फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है तो इससे जुड़े जोखिम समझना भी जरूरी हो जाता है। मुंबई में रहने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ऋतेश भाटिया बताते हैं, 'फास्टैग हासिल करने के लिए आपको अपनी निजी जानकारी उपलब्ध करानी या अपलोड करनी पड़ती है। इसमें आपके केवाईसी से जुड़े दस्तावेज, छायाचित्र और मोबाइल नंबर शामिल होते हैं। इस जानकारी की सुरक्षा का जिम्मा इस पूरी प्रणाली में शामिल हरेक पक्ष पर होता है। सुरक्षा में कहीं भी चूक हो गई तो पहचान की चोरी का खतरा खड़ा हो जाएगा। साथ ही ऐसा लगता है कि टोल बूथ पर लगे कैमरे वहां से गुजरने वाली कारों और उनमें बैठे चालकों की तस्वीर ले लेते हैं। इन तस्वीरों को भी पूरी तरह महफूज रखने की जरूरत है। यह पूरी तकनीक एक तरह से आपके वाहन का 'आधार' यानी पहचान है। इसीलिए इसमें शामिल सभी पक्षों को निजता की सुरक्षा का पूरा खयाल रखना चाहिए।' ऊपर बताई गई बातों का ध्यान उन संस्थाओं को रखना चाहिए, जो इस पूरी व्यवस्था में शामिल हैं। लेकिन आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? याद रखिए कि आप अपने फास्टैग को बैंक में पहले से चल रहे अपने बचत या चालू खाते से जोड़ सकते हैं और आपके पास उसे किसी प्रीपेड खाते से जोड़ने का विकल्प भी मौजूद है। कोई भी तकनीक 100 फीसदी अभेद्य नहीं होती यानी हर जगह सेंध लग सकती है। इसीलिए बेहतर है कि बाद में पछताने के बजाय पहले ही अपनी हिफाजत का पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए अपने फास्टैग को बैंक के बचत या चालू खाते से जोड़ने के बजाय प्रीपेड कार्ड से जोड़ना बेहतर रहेगा। अगर आपने पूरा केवाईसी करा लिया है तो आप प्रीपेड कार्ड में 1 लाख रुपये तक की रकम लोड कर सकते हैं, जो लंबे अरसे तक आपकी टोल भुगतान की जरूरत पूरी करती रहेगी।

महाराष्ट्र में आरक्षण का दांव

सरकार बोली, स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण मिलेगा

एजेंसियां

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाडी सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोश्यारी ने विधानसभा भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने आने वाले वर्षों के लिए सरकार का व्यापक एजेंडा पेश किया।

कोश्यारी ने कहा कि सरकार आम लोगों को 10 रुपये में भोजन मुहैया कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देना, दस रुपये में भोजन मुहैया कराना और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण सत्तारूढ़ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है। कोश्यारी ने मराठी में अपने भाषण में कहा, 'शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महाविकास आघाडी गठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।' उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की 'सही तस्वीर' पेश करेगी।

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भाजपा प्रत्याशी किशन कथोरे के सुबह नामांकन वापस लेने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप वालसे पाटिल ने यह घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया है ताकि विधानसभा अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन की राज्य की परंपरा कायम रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे खुशी है कि एक किसान का बेटा इस पद पर आसीन हुआ है।

पटोले ने भाजपा के हरीभाऊ बागड़े का स्थान लिया जो 2014 से 2019 के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। पटोले ने साल 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फडणवीस से मतभेद का हवाला देते हुए वर्ष 2017 में भाजपा छोड़कर दोबारा कांग्रेस में लौट आए थे। सदन

विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल कोश्यारी का स्वागत करते मुख्यमंत्री ठाकरे पीटीआई

से किसानों की समस्याओं को कम करने की अपील करते हुए ठाकरे ने कहा, इस सरकार का उद्देश्य न केवल किसानों का कर्ज माफ करना है बल्कि हमें उनकी परेशानियों को भी कम करने की जरूरत है।

ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव से पहले किए गए दावे 'मी पुन्हा एईं' (मैं वापस लौटूंगा) पर भी कटाक्ष किया। ठाकरे ने अपने बधाई संदेश में कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं इस सदन में आया। उन्होंने कहा, मैं सदन और महाराष्ट्र के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं कुछ भी आधी रात को नहीं करूंगा। मैं लोगों के हितों के लिए काम करूंगा।

राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य के विभागों में महापोर्टल के बजाय लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के जरिए भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। ठाकरे को शनिवार को भेजे पत्र में सुले ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार महापोर्टल के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों के लिए भर्तियां करती थी। महापोर्टल को इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। पुणे की बारामती सीट से लोकसभा सांसद ने कहा, 'लेकिन इससे हमेशा असुविधा ही हुई है।' उन्होंने दावा किया कि सरकारी नौकरियां पाने के इच्छुक कई युवकों को पिछले पांच वर्षों में दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने कहा, 'यह बेहतर होगा अगर भर्तियां पूर्व की प्रक्रिया (एपीएससी) के अनुसार की जाए।'

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले को बधाई देते हुए फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फसल नुकसान के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये दिए जाने की पहले जो मांग करते थे, उसे अब उन्हें पूरा करना चाहिए।

फडणवीस ने हालिया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'भाजपा को जनादेश मिला क्योंकि हमारी पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। 1 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट 70 प्रतिशत का रहा लेकिन राजनीतिक गुणागणित योग्यता पर भारी पड़ा।'

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार शनिवार को राज्य विधानसभा में बहुमत परीक्षण में कामयाब रही। कुल 288 सदस्यों वाले सदन में मतदान से पहले भाजपा के 105 विधायकों के सदन से बहिर्गमन के बाद 169 विधायकों ने विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया। विधायक के तौर पर फडणवीस (49) का यह पांचवां कार्यकाल है जबकि पटोले का चौथा कार्यकाल है। इससे पहले शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर अपने पूर्व सहयोगी भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनाई है।

साइबर सुरक्षा नीति में बदलाव करेगी सरकार

नेहा अलावधी

करीब सात साल बाद भारत अपनी साइबर-सुरक्षा नीति को उन्नत करने जा रहा है। राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा रणनीति 2020 की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाते हुए सरकार ने लोगों से इस बारे में राय आमंत्रित की है।

राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा रणनीति (एनसीएसएस) की वेबसाइट पर जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 2020 से अगले पांच वर्षों के लिए नई रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत एक कार्यबल भी गठित किया गया है। एनसीएसएस के मुताबिक इसके बारे में लोग 31 दिसंबर तक अपनी राय दे सकते हैं। वेबसाइट के अनुसार, एनसीएसएस 2020 का मकसद एक सुरक्षित, विश्वस्त, लचीला एवं फुर्तीला साइबर जगत तैयार करना है जिससे भारत की समृद्धि को मजबूती दी जा सके।

साइबर-सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए राजेश पंत पिछले कुछ दिनों में एनसीएसएस-2020 को लेकर कई बार जिक्र कर चुके हैं। इसके पहले वर्ष 2013 में भारत की साइबर-सुरक्षा नीति आई थी।

एनसीएसएस वेबसाइट इस बात को मानती है कि मौजूदा साइबर खतरा गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी और 5जी जैसी तकनीक के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में डेटा सुरक्षा एवं निजता, विकसित हो रहे साइबर जगत में कानून प्रवर्तन, विदेशों में रखे डेटा तक पहुंच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग, साइबर-अपराध एवं साइबर आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसी नई चुनौतियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने भारत के लिए साइबर-सुरक्षा का एक रोडमैप तैयार किया था। इसमें वर्ष 2025 तक भारतीय साइबर सुरक्षा उत्पाद एवं सेवा उद्योग का आकार 35 अरब डॉलर तक पहुंचाने की मंशा जताई गई है। इस प्रक्रिया में 10 लाख रोजगार अवसर और साइबर-सुरक्षा में सक्रिय 1,000 स्टार्टअप भी खड़े होने की बात कही गई है।

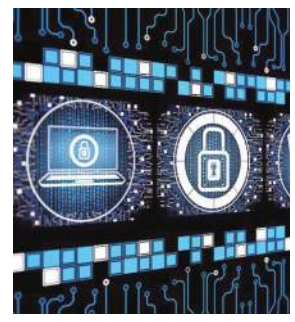

नई तकनीकों के आने से बढ़ा है साइबर सुरक्षा का खतरा